

कौमी पत्रिका

राष्ट्रीय दैनिक अखबार

R.N.I. No. UP-HIN/2007/21472 सम्पादक - गुरचरन सिंह खड्कर वर्ष 19 अंक 112 qaumipatrikahindi 011-41509689, 23315814, 9312262300 गाजियाबाद संवत् 2077-78, पेज (12) मूल्य 3.00 रुपये (हवाई शुल्क 50 पैसे अतिरिक्त)

VISIT:
www.qaumipatrika.in
Email: qpatrika@gmail.com

प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा 25-26 फरवरी को

नेतन्याहू के साथ व्यापक वार्ता करेंगे

विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी स्थानीय समयानुसार बुधवार सुबह 12:45 बजे तेल अवीव पहुंचेंगे

एजेंसी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 फरवरी से इजराइल की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वह अपने इजराइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इजराइली संसद नेसेट को संबोधित भी करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी स्थानीय समयानुसार बुधवार सुबह 12:45 बजे तेल अवीव पहुंचेंगे। आमन पर दोनो प्रधानमंत्रियों के बीच संक्षिप्त मुलाकात होगी। पहले दिन प्रधानमंत्री नेसेट को संबोधित करने के अलावा



भारतीय मूल के लोगों के साथ एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का दौरा करेंगे। राजि में वह प्रधानमंत्री नेतन्याहू

द्वारा आयोजित निजी रात्रिभोज में शामिल होंगे। यात्रा के दूसरे दिन 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी यरशलम स्थित याद वशेम जाकर हेरोलोकॉस्ट स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जहां नाजी अत्याचारों में मारे गए लाखों यहूदियों की स्मृति संरक्षित है। इसके बाद प्रधानमंत्री इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनो देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी होगी। वार्ता के बाद नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कई

महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान भारतीय और यहूदी समुदाय के सदस्यों के साथ भी संवाद करेंगे। यह यात्रा रणनीतिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले नौ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा इजराइल दौरा होगा और दोनो देशों के बीच 'गणनीतिक साझेदारी' को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।

कांग्रेस की हर गतिविधि हमारे लिए आशीर्वाद: हिमंत बिस्वा सरमा

एआई शिखर सम्मेलन मामला

बड़ा खुलासा, सुनियोजित साजिश के तहत हुआ हंगामा

कई राज्यों से जुड़े तार, आठ गिरफ्तार

एजेंसी नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 24 फरवरी 2026 को एआई शिखर सम्मेलन के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदर्शन मामले पर पहली बार आधिकारिक बयान दिया है। विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने मीडिया के सामने यह जानकारी साझा की। इस संवेदनशील मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गई है। **भारत मंडप में हुआ था बवाल** अपराध शाखा की अंतरराज्यीय प्रकोष्ठ इस पूरे मामले की महनता से जांच करेगी। यह घटना 20 फरवरी को भारत मंडप में हुई थी, जहां

प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया था। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थीं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। तिलक मार्ग थाने में इस संबंध में एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया था। **अबतक आठ गिरफ्तार** पुलिस ने बताया कि आरोपियों को निगरानी कैमरे के फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा गया है। जांच से पता चला है कि कई लोग इन आक्रामक तत्वों को बाहर से सहायता प्रदान कर रहे थे। अब तक इस मामले में कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई है।

जांच का दायरा और कानूनी कार्रवाई

प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 191 (1) और 192 जोड़ी गई हैं। वे धाराएं मुख्य रूप से दंगा भड़काने और अपराधिक घड़ंतंत्र से संबंधित हैं। अपराध शाखा मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। इसका उद्देश्य घटना के पीछे के सभी राजसिक्ताओं का पता लगाना है।

पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

केंद्र ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने को दी मंजूरी

यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत पूरी की जाएगी

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य 'केरल' का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय राज्य सरकार के अनुरोध और विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। सरकार के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति अब केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल की राज्य विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजेंगे। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत पूरी की जाएगी। राज्य विधानसभा से प्राप्त सुझावों और विचारों के बाद भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। इसके पश्चात राष्ट्रपति की सिफारिश लेकर केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को संसद में पेश किया जाएगा। दरअसल, केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर राज्य का नाम 'केरल' से बदलकर 'केरलम' करने की सिफारिश की थी। इसके बाद केरल सरकार ने भारत सरकार से संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर नाम परिवर्तन करने का औपचारिक अनुरोध किया था। यदि संसद इस विधेयक को पारित कर देती है, तो आधिकारिक रूप से राज्य का नाम 'केरलम' हो जाएगा।



बिहार विधानसभा में भड़के नीतीश

विपक्षी सदस्यों से कहा- बेमतलब का नहीं बोलिए, चुप बैठिए

एजेंसी पटना। बिहार में दफादार और चौकीदारों पर हुए लाठीचार्ज की घटना ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे दफादार और चौकीदारों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मामला इतना बढ़ गया कि इसकी गुंज बिहार विधानसभा तक पहुंची और सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार विधानसभा में अपनी जगह से खड़े हुए और कहा, 'बेकार का हो-हल्ला मत कीजिए, आप लोग कभी कोई काम किए हैं क्या?' नीतीश कुमार ने विपक्षी सदस्य भाई वीरेंद्र और कुमार सर्वजीत को इशारा करते हुए कहा कि चुपचाप बैठिए। नीतीश कुमार ने विपक्ष की संख्या पर भी तंज कसते हुए कहा, 'आप लोग अपनी संख्या देख लीजिए और हमारी संख्या देख लीजिए। हम आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन बिना

मतलब की बातें मत कीजिए।' इसी दौरान जब राजद विधायक भाई वीरेंद्र बोलने लगे तो नीतीश कुमार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार



लगातार विपक्ष की बात सुनती है, लेकिन बेवजह आरोप लगाने से बचें। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए विधायकों की संख्या 202 की जगह 2002 बता दी। इस दौरान नीतीश कुमार विधायकों को बार-बार मीटिंग कहते नजर आए। सीएम ने कहा, 'एक-दो बार तो हमने आप लोगों को रखकर गलती की, लेकिन

आप लोग इधर-उधर करने लगे तो साथ छोड़ दिया। आपको सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है, जो भी काम हुआ है, वह हमारी सरकार के समय में हुआ है।' नीतीश कुमार के लगातार इस एवधान को लेकर उनके बगल की सीट पर बैठे संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी यह कहते हुए नजर आए कि बैठ जाइए। इसके बाद भी सीएम अपनी बात कह रहे थे। हालांकि, विपक्ष के विधायकों ने हंगामा बंद किया तो नीतीश कुमार भी अपनी जगह पर बैठ गए।

केंद्र ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिल्वर एक्सेल के विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 1,677 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसके पूरा होने पर हवाई अड्डे की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नए सेवा तीर्थ में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। वैष्णव ने बताया कि 73.18 एकड़ क्षेत्र में 71,500 वर्ग मीटर का नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा, जिसमें 20,659 वर्ग मीटर मौजूदा संरचना का उपयोग होगा। विमान पार्किंग क्षेत्र का विस्तार कर 15 विमान पार्किंग बे बनाए जाएंगे, जिनमें एक वाइडबॉडी (कोड ई) बे भी शामिल होगा। मल्टी-लेवल कार पार्किंग सुविधा में 1,000 कारों की क्षमता होगी। नया टर्मिनल पीक आवर्स में 2,900 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और इसकी वार्षिक क्षमता 10 मिलियन यात्रियों तक होगी। परियोजना को 5-स्टार ग्रिहा (एकीकृत आवास मूल्यांकन की हदित रेटिंग) रेटिंग हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ निर्माण पर जोर दिया जाएगा।

अग्रिम जमानत के लिए

उच्च न्यायालय पहुंचे

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकराचार्य ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की

एजेंसी लखनऊ। यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब अपनी अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दस्तक दी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकराचार्य ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। शंकराचार्य ने अधिवक्ता जर्जाई गुप्ता, सुभांशु कुमार और श्री प्रकाश के जरिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता जर्जाई गुप्ता, सुभांशु कुमार और श्री प्रकाश के जरिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। दरअसल, तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 173 (4) के तहत जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई के बाद एडीजे रेप एंड पीक्सो स्पेशल कोर्ट विनोद कुमार चौरसिया ने झूठी पुलिस को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत अन्य संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसे में शंकराचार्य और उनके साथी संतो की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।



2026-27 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी

सरकार के इस फैसले से पूरे भारत में उत्पादन की औसत लागत पर 61.8 फीसदी का रिटर्न मिलेगा।

एजेंसी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंगलवार को (सीसीईए) विपणन सीजन 2026-27 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नए 'सेवा तीर्थ' में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सीसीईए ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) का एमएसपी 5,925 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने



लिए कच्चे जूट का एमएसपी पिछले विपणन सीजन 2025-26 के मुकाबले 275 रुपये प्रति क्विंटल

ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी विपणन सीजन 2014-15 के 2400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर विपणन सीजन 2026-27 में 5,925 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो 3,525 रुपये प्रति क्विंटल यानी (2.5 गुना) की बढ़ोतरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपणन सीजन 2014-15 से विपणन सीजन 2025-26 के दौरान जूट उगाने वाले किसानों को दी गई एमएसपी रकम 1342 करोड़ रुपये थी, जबकि विपणन सीजन 2004-05 से विपणन सीजन 2013-14 के दौरान दी गई रकम 441 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि सरकार के

इस फैसले से पूरे भारत में उत्पादन की औसत लागत पर 61.8 फीसदी का रिटर्न मिलेगा। विपणन सीजन 2026-27 के लिए कच्चे जूट का घोषित एमएसपी बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित पूरे भारत में उत्पादन की औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुसार है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जूट कृषि पर आर्थिक इंडिया (जेसीआई) ग्राइस सपोर्ट ऑपरेशन करने के लिए केंद्र सरकार को नोडल एजेंसी बननी रहेगी और ऐसे ऑपरेशन में अगर कोई मुकसान होता है तो केंद्र सरकार उसकी पूरी भरपाई करेगी।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने संजय सरावगी की माता को दी श्रद्धांजलि

बैठक में राज्यसभा की पांच सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की गई।

एजेंसी पटना/दरभंगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को दरभंगा पहुंचे। वे दरभंगा शहर से भाजपा विधायक-सह प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की दिवंगत माता जी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और उन्हें नमन किया। इससे पहले मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा हवाईअड्डे पर उनके पहुंचते ही 'जय श्री राम', 'भारत माता की जय' और 'नितिन नवीन जिंदगाद' के नारों से माहौल गुंज उठा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। बिहार के उपमुख्यमंत्री स्मार्ट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने आगे बढ़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। उन्हें फूल-मालाएं पहनाई गईं और शाल ओझाकर अभिनंदन किया गया। हालांकि, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और सोधे प्रदेश अध्यक्ष के आवास के लिए रवाना हो गए। संजय सरावगी की माता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नितिन नवीन दरभंगा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा की कोर कमेटी की

बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्यसभा की पांच सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को



लेकर चर्चा की गई। बैठक में संगठन महामंत्री भीरू भाई दलसानिया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री स्मार्ट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, पूर्व मंत्री जीवेश कुमार तथा राज्यसभा सदस्य डॉ. धर्मशिला गुप्ता मौजूद रहे।

राहुल गांधी भारत को शर्मिंदा करने की साजिश में बेनकाब : गौरव माटिया

एजेंसी नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव माटिया ने मंगलवार को आरोप लगाया कि एआई शिखर सम्मेलन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने की साजिश रची, जो अब परत-दर-परत सामने आ रही है। भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में माटिया ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडप में विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एआई समिट के दौरान, जब पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी, उस समय युवा कांग्रेस ने टी-शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। माटिया ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा और बदनाम करने

अकाली और कांग्रेस सरकारों ने पंजाब के बच्चों को जानबूझकर अनपढ़ रखा: भगवंत मान

कौमी पत्रिका मानसा, 24 फरवरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि अकाली और कांग्रेस के दशकों के शासन ने जानबूझकर पंजाब के बच्चों को अनपढ़ रखा, जबकि राजनीतिक परिवार फलते-फूलते रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन पार्टियों को कभी भी लोगों की तरकीबों की चिंता नहीं थी, बल्कि सिर्फ अपनी बेटीयों-बेटों और रिश्तेदारों के लिए सत्ता हासिल करने की चिंता थी। सरदूलगढ़ में सरकारी आई.टी.आई., जो हर साल 240 विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाएगा, का नींव पत्थर रखने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा अब चुनाव सपना पूरा करने के लिए दूसरी पार्टियों के दलबदलुओं पर निर्भर कर रही है लेकिन पंजाब ने अलग रास्ता चुना है। पंजाब सरकार द्वारा सरकारी खजाने का

एक-एक पैसा ईमानदारी से लोगों की भलाई और तरकीबों पर खर्च करने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐलान किया कि 'आप' सरकार, पंजाब विकास के लिए नए इंजन पर चल रही है, जबकि भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस के इंजन पुराने हो चुके हैं और सबे को आगे बढ़ाने के सक्षम नहीं हैं। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, अकाली दल एक डायनासोर है, जिसने राज्य और इसके लोगों की कमाई को हड़प लिया। जहां 'आप' सरकार पंजाबी नौजवानों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाकर भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सख्त प्रयास कर रही है, वहीं अकाली दल राज्य के नौजवानों को डायनासोर युग में वापस खींचने पर तुला हुआ है। उन्होंने लोगों को बंद दिलाया कि डायनासोर मनुष्यों के लिए घातक थे। उन्होंने कहा कि

डायनासोर अकालियों का पसंदीदा जानवर है क्योंकि

को नहीं चुनेंगे, जिन्होंने राज्य को बर्बाद किया है और अपनी धिनीनी हरकतों से हमारी पीढ़ियों को हड़प लिया है। अकाली दल की पंजाब बचाओ यात्रा पर व्यंग्य कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली दल की इस चाल का असली नाम 'परिवार बचाओ यात्रा' है। उन्होंने कहा, मैं अकाली नेताओं को चुनौती देता हूँ कि वे यह बताएं कि 15 साल राज्य को लूटने के बाद वे राज्य को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने अकालियों को चुना था लेकिन वे गद्दार साबित हुए और हमेशा सूबे और इसके लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों को याद दिलाया कि जब समूची किसानी मान हकों के लिए लड़ रही थी तब अकालियों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी कुर्सी बचाने खातिर काले कृषि कानूनों पर मोदी सरकार का समर्थन



अकालियों ने भी पंजाब और पंजाबियों की मेहनत की कमाई खाई है। उन्होंने कहा, लोग कभी भी ऐसे नेताओं

किया था। उन्होंने कहा कि अकालियों ने अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए पंथ की दुरुपयोग किया है, जिस कारण लोगों द्वारा उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी चुनाव जीतने की उम्मीद में दूसरी पार्टियों के दलबदलुओं पर निर्भर कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, भाजपा की यह रणनीति पंजाब में काम नहीं करेगी क्योंकि दूसरी मशीनों के खराब हुए पुर्जों वाला इंजन ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां उनसे जलन रखती हैं क्योंकि वे यह हजम नहीं कर पा रही हैं कि एक आम आदमी का बेटा राज्य का शासन प्रभावशाली हो से चला रहा है। उन्होंने आगे कहा, पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों के लोग विरोधी और पंजाब विरोधी रुख कारण पंजाब को लगे का उनसे विश्वास उठ गया है।

शेष पृष्ठ 3 पर

विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कुलपति को सौंपा ज्ञापन

एजेंसी
जौंद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुविधा, सुरक्षा एवं समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग को लेकर वीसी प्रो. डॉ. रामपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय जिम में महिला ट्रेनर की शीघ्र नियुक्ति की मांग की गई। एनएसयूआई के विश्वविद्यालय अध्यक्ष जयदीप सिंधु ने कहा कि वर्तमान समय में विश्वविद्यालय में बढ़ी संख्या में छात्राएं अध्ययन कर रही हैं और वे नियमित रूप से खेल व फिटनेस गतिविधियों में भाग लेना चाहती हैं लेकिन जिम में महिला ट्रेनर की अनुपस्थिति के कारण कई छात्राएं असहज महसूस करती हैं। जिससे वे जिम सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रही हैं। यह स्थिति छात्राओं के आत्मविश्वास और शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। जयदीप सिंधु ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का दायित्व है कि वह छात्राओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और सहज वातावरण प्रदान करे। महिला ट्रेनर की नियुक्ति से न केवल छात्राओं की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि विश्वविद्यालय में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया तो संगठन छात्राहट में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर सुशील सिहाग, अजमेर, मनजोत, अनुज कुंडू, रिंकी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गीता यूनिवर्सिटी की कैटैन में लगी भीषण आग में कुक का हाथ झुलसा

पानीपत। पानीपत स्थित गीता यूनिवर्सिटी परिसर में रविवार की रात कैफे में भीषण आग लग गई। आग गैस सिलेंडर फटने के कारण लगी आग से अफरातफरी मच गई। शुरुआत में लपटे कम होने के कारण वहां मौजूद लोग फायर यंत्र से काबू पाने की कोशिश की गई लेकिन तभी सिलेंडर गम होने के कारण फट गया जिससे खाना बना रहे कुक का हाथ झुलस गया। सिलेंडर फटने के कारण हुए धमाके से मौके पर मौजूद दर्जनों छात्र-छात्राओं ने भागकर अपनी जान बचाई। धमाका इतना तेज था कि कैफे की छत और फर्नीचर के अवशेष हवा में दूर दूर तक बिखर गए। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। साथ ही फायर ब्रिगेड को आग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से प्रारंभिक तौर पर आग का कारण 'शॉर्ट सर्किट' बताया गया है। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत पाई गई, जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों की एक छोटी सी लापरवाही इस बड़े हादसे का कारण बनी। बताया जा रहा है कि रसोई में काम के दौरान गैस का एक बर्नर या पाइप खुला रह गया था, जिससे गैस का रिसाव होने लगा। देखते ही देखते कैफे के भीतर आग की लपटें उठने लगीं।

हर घर का कनेक्शन होगा वैध, मिलेगा नहरी पानी

जौंद। जौंद शहर में हर घर तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में काम कर रही है। इसके लिए जहां महत्वपूर्ण परिवोजना का काम बड़ोटी गांव में बड़ी जोर-शोर से चल रहा है, वहीं शहर में सभी घरों का पेयजल कनेक्शन नियमित करने के लिए विभाग द्वारा जोरदार अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह की टीम हर घर का कनेक्शन वेरिफिकेशन के लिए सर्वे करके नए कनेक्शन का डाटा अपलोड कर रही हैं वहीं विभाग की टीमें अवैध कनेक्शन पर शिकंजा के लिए नोटिस व घर घर जाकर दस्तक दे रही हैं। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जिला सलाहकार रणधीर मताने ने नेताजी कॉलोनी में टीमों का अवलोकन करने के बाद कार्य में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने बताया कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन की टीमों द्वारा जौंद शहर के हर घर का सर्वे स्वयं सहायता समूह की सहयता से करवाया जा रहा है। इस सर्वे के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि उपभोक्ता का पेयजल कनेक्शन नियमित है या नहीं। कनेक्शन का वेरिफिकेशन के लिए उपभोक्ता से आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पेयजल नल का फोटो व अन्य जरूरी कागजात लेकर विभाग की साइट पर अपलोड किया जा रहा है ताकि सभी पेयजल कनेक्शन की वेरिफिकेशन की जा सके। इसके बाद जो नए कनेक्शन हैं, उन्हें विभाग द्वारा नियमित किया जाएगा।

किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक पैसा हैं सुरक्षित : नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मामले में कहा कि हरियाणा सरकार के विभागों की जागरूकता से यह मामला सामने आया और इस पर सरकार ने तत्काल बैंक को डि-एम्पैनल कर दिया। बैंक द्वारा जो स्टेटमेंट उपलब्ध कराए गए, वे-विभागीय स्टेटमेंट से मेल नहीं खाते थे। राज्य सरकार गंभीरता से इस मामले की जांच करवा रही है। सरकार ने ये मामला राज्य के एटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा है। इसके अलावा, इस पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में और पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेबी को पत्र लिखा, जिसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ किए जाने की बात कही। इस मामले में बैंक ने भी अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर रखी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लेनदेन में मिली अनियमितताओं के सम्बंध में एफआरओए दर्ज हो गयी है। बैंक ने इस सम्बंध में 21 फरवरी को पत्र लिखा था, जबकि जैसे ही यह मामला राज्य सरकार के संज्ञान में आया तो सरकार ने पहले ही 18 फरवरी को बैंक को डि-एम्पैनल करते हुए ब्याज सहित पैसा राष्ट्रीय बैंक में ट्रांसफर करने के लिए कह दिया था, पैसा पूरा सुरक्षित है।

विधानसभा में प्रस्ताव खारिज होने पर कांग्रेस ने किया वाकआउट

एजेंसी
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस ने एचपीएससी व एचएसएससी की भर्तियों पर दिए गए काम रोकने प्रस्ताव के मुद्दे पर हंगामा कर दिया। स्पीकर ने इसे तत्कालिक विषय न होने के चलते रद्द कर दिया। इसे लेकर सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा। स्पीकर हरविन्द कल्याण ने कहा कि कांग्रेस का प्रस्ताव आया है और वह विचाराधीन है। गीता भुक्कल के साथ आफताब अहमद, अशोक अरोड़ा शकुंतला खटक, जस्सी पेटवाड़, बलराम दांगी, नरेश सेलवाल, देवेन्द्र हंस सहित कई विधायकों ने सभी काम रोककर पहले चर्चा करवाने की मांग उठाई। शोर-शराबे के बीच स्पीकर हरविन्द कल्याण ने कहा कि विषय आज और अभी प्रस्ताव पर फैसला चाहता है। स्पीकर ने कहा कि मैंने प्रस्ताव रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में 11 वर्षों की भर्तियों का मुद्दा उठाया है। ऐसे में यह तत्काल चर्चा का विषय नहीं है।

उन्के प्रस्ताव रिजेक्ट करते ही कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस विधायकों ने प्रस्ताव मंजूर करने की मांग करते हुए रहे। स्पीकर हरविन्द कल्याण ने अपनी सीट से उठकर उन्होंने सभी को बैठाया भी और शांत रहने का अनुरोध भी किया। फिर भी नारेबाजी जारी रही। संसदीय कार्य मामले मंत्री एजेंसी **चंडीगढ़।** हरियाणा के अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ के हजारों पद खाली पड़े हैं। रनिंयां से इनलो विधायक अर्जुन चौटाला के प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विस्तृत रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कई महत्वपूर्ण श्रेणियों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। सिविल सर्जन व समकक्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के 51 में से 22 पद खाली हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 644 में से 210, मेडिकल ऑफिसर के 4054 में से 541 रिक्त, दंत चिकित्सक के 725 में से 87 रिक्त, एमपीएचडब्ल्यू (फिमले) के 2724 में से 779 खाली तथा एलटी (जी) के 11335 में से 407 रिक्त हैं। इसी तरह स्टाफ नर्स/नर्सिंग ऑफिसर के 5039 में से 653 खाली खाली हैं। फार्मसी ऑफिसर के 1085 में से 385 पद

एसीबी करेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले की जांच : मुख्यमंत्री

एजेंसी
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से हुई 590 करोड़ रुपये के अधिक की धोखाधड़ी मामले की जांच एटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की जाएगी। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले में आरोपित अधिकारियों व कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट मांगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में एलान किया कि सरकार इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है। एटी करप्शन ब्यूरो और बिजिलेंस विभाग को इस मामले की जांच का



जिम्मा सौंपा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों व बोर्ड-निगमों को धांधली को भी सरकार ने ही पकड़ा है। चार-पांच दिनों से सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि बैंक को 18 फरवरी डी-इम्पैनल कर दिया गया है। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बाद ही

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेबी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले से अवागत करवाया है। बैंक ने अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। सीएम ने कहा कि सरकार दोषियों को किसी सूत्र में बख्शेगी नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार का एक रुपया भी कहीं नहीं जाएगा। सारा पैसा सुरक्षित है और ब्याज समेत वापस आएगा। नायब सैनी ने कहा कि 590 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये के लगभग की एफडी थी। बाकी पैसा खातों में था। सीएम ने कहा कि वित्त विभाग को जब गड़बड़ नजर आई तो हिसाब-किताब का मिलान किया गया। इसमें कमी दिखी तो कार्रवाई शुरू हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पैसा भी दूसरी सरकारी बैंकों में ट्रांसफर करवा दिया है।

गुप ए व बी के कर्मचारियों को अमी नहीं मिलेगा प्रमोशन में आरक्षण

एजेंसी
चंडीगढ़। हरियाणा में अनुसूचित जाति से संबंधित गुप ए व बी के अधिकारियों को प्रमोशन में बीएस प्रतिशत आरक्षण के लिए अभी इंतजार करना होगा। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा में सटौरा की विधायक रेनु बाला ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर सवाल पूछा। विधायक ने इस मुद्दे पर पॉलिसी को लेकर लिए गए फैसले की जानकारी भी मांगी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सदन में बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा गुप ए तथा बी के अधिकारियों व कर्मचारियों को पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए सात अक्टूबर 2023 को आदेश जारी किए गए थे। उक्त नीति को सीडब्ल्यूपी संख्या 24608/2023 कमलजोत सिंह

एवं अन्य बनाम हरियाणा सरकार के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। एक अप्रैल 2025 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका को निरस्त करते हुए निर्देश दिए कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से पूर्व क्रीमी लेयर के सिद्धांत का अनुपालन करना सुनिश्चित करे। सरकार इस मामले में विचार कर रही है कि अब इसमें अपील दायर की जाए अथवा या नहीं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पहले से ही निर्देशों के तहत गुप डी व सी के पदों पर पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रही है। सरकार के जवाब से अस्तुष्ट विधायक ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को न तो एक साल में लागू किया गया है और न ही अगली याचिका दायर हुई है। कर्मचारी व अधिकारी लाभ से वंचित हो रहे हैं। इस बीच कई अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

सोनीपत जिला अस्पताल में उज्जत स्वास्थ्य सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध होंगी

एजेंसी
सोनीपत। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विधान सभा में कहा कि सोनीपत के जिला अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे मशीन, उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस और एमआरआई स्कैन सेवाएं शीघ्र शुरू की जाएगी। साथ ही हृदय रोग उपचार के लिए हृदय कैथेटर प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव विचारधीन है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोनीपत विधायक निखिल मदान के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सोनीपत में 200 बिस्तरों वाला जिला नागरिक अस्पताल रॉस्टो राजमार्ग 44 के निकट लगभग 15.5 एकड़ भूमि पर स्थित है, जिसमें से लगभग 6 एकड़ में भवन निर्मित है। इसके अतिरिक्त

138 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु देखभाल खंड निर्माणाधीन है। इसके पूर्ण होने पर अस्पताल की कुल क्षमता 300 बिस्तर हो जाएगी। मौजूदा भवन की विशेष मरम्मत के लिए 5.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अस्पताल में चिकित्सा, छाती रोग, सामान्य शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग, स्त्री रोग, नेत्र रोग, कर्ण-नाक-गला, बाल रोग, विकृति विज्ञान, ल्वचा रोग तथा संज्ञाहरण सहित विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हैं संगणित टोमोग्राफी जांच और वृक्क शोधन सेवाएं सार्वजनिक-निजी सहभागिता पद्धति के अंतर्गत अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, सी-आरम मशीन, विद्युत दाह यंत्र, संज्ञाहरण मशीन तथा गहन चिकित्सा कक्ष के बिस्तर स्थापित किए गए हैं।

रिफाइनरी में अपनी मांगो को लेकर धरने पर बैठे मजदूरों व सीआईएसएफ में टकराव, लाठीचार्ज

एजेंसी
पानीपत। पानीपत रिफाइनरी में अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों व अर्धसैनिक बलों के बीच टकराव हो गया। मजदूरों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। मजदूर ओवरटाइम, अधिकारियों के दुर्व्यवहार समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उनसे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की बात कही। इसके बाद, मजदूर लाठी-डंडों से लैस होकर आगे बढ़ने लगे। कुछ मजदूरों ने पथराव किया और निर्माणधीन प्रोजेक्ट के पास खड़ी कई गाड़ियों को पलट दिया। वहां 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी रिफाइनरी

पहुंच गई। पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर माहौल को शांत करने की कोशिश की। करीब डेढ़ घंटे बाद मामला शांत हुआ। मजदूर अभी भी साइटों पर काम कर रहे हैं। सभी मजदूरों ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। सुबह मजदूर गेट नंबर चार के पास धरने पर बैठ गए। अधिकारियों के पास पहुंचकर मामला शांत कराया। डीएसपी सिटी राजबीर ने कहा कि मजदूरों ने कुछ मांगों को लेकर आज हड़ताल का ऐलान किया था। हड़ताल के दौरान यहां माहौल कुछ गरमा गया। मौके पर पुलिस ने कानून व्यवस्था को संभाल लिया है। साथ ही मजदूरों के पदाधिकारियों से बात की गई है। उन्होंने अपनी कुछ मांगों लिखित रूप में दी हैं। अभी माहौल शांतिपूर्वक है। उन्होंने बताया कि मजदूरों द्वारा दिए गए मांग पत्र में कहा है कि जब-जब उनकी सैलरी आती है तो वो बेहिसाब कटौती के साथ मिलती है।

साइटों पर काम कर रहे हैं। सभी मजदूरों ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। सुबह मजदूर गेट नंबर चार के पास धरने पर बैठ गए। अधिकारियों के पास पहुंचकर मामला शांत कराया। डीएसपी सिटी राजबीर ने कहा कि मजदूरों ने कुछ मांगों को लेकर आज हड़ताल का ऐलान किया था। हड़ताल के दौरान यहां माहौल कुछ गरमा गया। मौके पर पुलिस ने कानून व्यवस्था को संभाल लिया है। साथ ही मजदूरों के पदाधिकारियों से बात की गई है। उन्होंने अपनी कुछ मांगों लिखित रूप में दी हैं। अभी माहौल शांतिपूर्वक है। उन्होंने बताया कि मजदूरों द्वारा दिए गए मांग पत्र में कहा है कि जब-जब उनकी सैलरी आती है तो वो बेहिसाब कटौती के साथ मिलती है।



अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। रिफाइनरी के अंदर कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। यहां ठेकेदारों के अंतर्गत लगभग 40 हजार मजदूर अलग-अलग

उज्जत तकनीक से प्याज उत्पादन बढ़ाने की दिशा में पहल, किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण शुरू

एजेंसी
यमुनानगर। किसानों की आय वृद्धि और बागवानी फसलों में आधुनिक तकनीकों के विस्तार के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, सलारू की ओर से पांच दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। यह प्रशिक्षण एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के विभिन्न गांवों से आए कृषक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र दामला में किया गया। प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में सहायक निदेशक डॉ. सुधीर कुमार तथा तकनीकी अधिकारी विमलेश कुमारी ने किसानों का स्वागत करते हुए प्याज और लहसुन की उन्नत किस्मों, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्रणाली तथा संस्थान द्वारा संचालित

किसानो-मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदित्य प्रताप डबास ने बागवानी क्षेत्र में संस्थान के योगदान की

वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन लागत कम करने के साथ गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। मुख्य अतिथि उप-निदेशक कृषि डॉ. साराहा करते हुए किसानों को विभागीय योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों का लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं जिला उद्यान अधिकारी

डॉ. विरेन्द्र पुनिया द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार की अनुदान आधारित योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बागवानी फसलों को आय का मजबूत विकल्प बताया गया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. संदीप रावल ने कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा संचालित प्रशिक्षण, प्रदर्शन इकाइयों और तकनीकी मार्गदर्शन कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि वैज्ञानिक खेती अपनाने से किसानों की आमदनी में स्थायी वृद्धि संभव है। तकनीकी सत्र में वैज्ञानिक डॉ. चन्दन तिवारी ने प्याज की उन्नत प्रजातियों, उत्पादन प्रबंधन, रोग एवं कीट नियंत्रण, खरपतवार प्रबंधन तथा कई उपरत भंडारण तकनीकों पर विस्तार से जानकारी दी। आगामी सत्रों में सब्जी फसलों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण भंडारण और बाजार उन्मुख उत्पादन पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

माता अमृता देवी की प्रतिमा अनावरण की मांग पर इनसो का प्रदर्शन

एजेंसी
हिसार। यहां के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में माता अमृता देवी की प्रतिमा के अनावरण की मांग पर प्रदर्शन कर रही इनसो की छत्र इकाई इनसो व गुजवि प्रशासन के बीच विवाद हो गया। इनसो के प्रदेशाध्यक्ष साहित्यदीप कंसवा ने अपने समर्थकों के साथ सोमवार को विश्वविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। मामले के अनुसार इनसो ने कुछ दिन पूर्व ही चेतवनी दी थी कि यदि गुजवि प्रशासन माता अमृता देवी की प्रतिमा का अनावरण नहीं करवाता है तो संगठन अपने अनुसार बिस्नोई समाज की किसी छात्रा या महिला से यह कार्य करवाएगा। संगठन का आरोप है कि विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति कार्यालय की ओर जाने वाले मेन चौक पर खेजड़ी बलिदान की स्मृति में माता अमृता देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस चौक का निर्माण लगभग 6 माह पहले पूरा हो चुका है, लेकिन प्रतिमा अब तक ठकी हुई है और उसका अनावरण नहीं किया गया है। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रतिनिधियों की विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत कराई गई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद पुलिस ने एख्तियारतन कार्रवाई करते हुए साहित्यदीप कंसवा सहित 14 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उन्हें पुलिस बस से पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। साहित्यदीप कंसवा ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन उद्घाटन को राजनीतिक कार्यक्रम बनाना चाहता है और किसी बड़े नेता से इसका लोकार्पण करवाने की योजना बना रहा है। उन्होंने मांग की कि प्रतिमा का अनावरण बिस्नोई समाज की किसी छात्रा से कराया जाए। उल्लेखनीय है कि दिसंबर माह में सीएम सैनी का कार्यक्रम विश्वविद्यालय में प्रस्तावित था, जो बाद में रद्द हो गया था। इसी मांग पर इनसो ने प्रदर्शन किया है।

हरियाणा के अस्पतालों में मेडिकल व पैरामेडिकल के छह हजार पद खाली

एजेंसी
चंडीगढ़। हरियाणा के अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ के हजारों पद खाली पड़े हैं। रनिंयां से इनलो विधायक अर्जुन चौटाला के प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विस्तृत रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कई महत्वपूर्ण श्रेणियों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। सिविल सर्जन व समकक्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के 51 में से 22 पद खाली हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 644 में से 210, मेडिकल ऑफिसर के 4054 में से 541 रिक्त, दंत चिकित्सक के 725 में से 87 रिक्त, एमपीएचडब्ल्यू (फिमले) के 2724 में से 779 खाली तथा एलटी (जी) के 11335 में से 407 रिक्त हैं। इसी तरह स्टाफ नर्स/नर्सिंग ऑफिसर के 5039 में से 653 खाली खाली हैं। फार्मसी ऑफिसर के 1085 में से 385 पद

और फिजियोथेरेपिस्ट के 62 में से 57 पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में 6,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। मेडिकल ऑफिसर के 450 पद पहले ही विज्ञापित किए जा चुके हैं। एमपीएचडब्ल्यू (फिमले) के 700 पद, एलटी के 70 पद, स्टाफ नर्स के 348 पद और कई अन्य श्रेणियों के पद एचएसएससी और एचपीएससी को भेजे जा चुके हैं। सिविल सर्जन, एसएमओ तथा एमपीएचएस आदि के पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। रिपोर्ट में यह चौंकार वाला तथ्य भी सामने आया कि अक्सिडेंट मैटन (18 पद), चीफ नर्सिंग ऑफिसर (28 पद) तथा एचएन (121 में से 100 खाली) हैं। इन पदों पर योग्य उम्मीदवार कैडर में उपलब्ध ही नहीं हैं।

संयुक्त पंजाब के सबसे बुजुर्ग विधायक को सम्मानित करने की मांग

एजेंसी
चंडीगढ़। डबवाली से इनलो विधायक आदित्य देवीलाल ने 105 वर्षीय पूर्व विधायक सही राम बिस्नोई को विशेष सम्मान देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि संयुक्त पंजाब विधानसभा के ये पूर्व सदस्य न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के सबसे बुजुर्ग जीवित पूर्व विधायक हैं। इनलो विधायक आदित्य देवीलाल ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करके उन्हें आधिकारिक पत्र सौंपते हुए कहा कि 105 वर्ष की उम्र में भी सही राम बिस्नोई का व्यक्तित्व प्रेरणा का स्रोत है। उनका सम्मान केवल व्यक्ति का नहीं, हमारे इतिहास का सम्मान होगा। आदित्य देवीलाल ने बताया कि सही राम बिस्नोई ने लाहौर से लॉ की शिक्षा प्राप्त की। 1947 के आजादी आंदोलन में हिस्सा लिया और संयुक्त पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। आज 105 साल की उम्र में भी सक्रिय सोच और गहरी राजनीतिक समझ रखते हैं। उन्होंने कहा कि देश में इतनी आयु का कोई दूसरा जीवित

पूर्व विधायक नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे महान व्यक्तित्व को सम्मान दें, ताकि नई पीढ़ी भी प्रेरणा ले सके। वहीं विधानसभा में धरने और विवाद के लिए इनसो के पोर्टल गलत डेटा दिखा रहे हैं। सुधार करवाने को कोई अधिकारी जिम्मेदारी



शून्यकाल में बोलते हुए आदित्य ने जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पक्की नहरों का आउटलेट (मोबे) विभाग द्वारा ऊपर-नीचे किए जाते हैं, जिससे टेल के किसानों को पानी नहीं मिलता।

पारदर्शी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से शहर को मिलेगी अवैध कब्जों से मुक्ति: रणवीर सिंह

एजेंसी
नारनौल। नारनौल शहर का डिजिटल रिकॉर्ड दुरुस्त करने की दिशा में शहर का नक्शा प्रकल्प में अब दस और कॉलोनियों को शामिल किया गया है। इस पारदर्शी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के बनने से शहर को अवैध

कब्जों से मुक्ति मिलने के साथ-साथ विकास को एक नई गति भी मिलेगी। जिला नगर आयुक्त रणवीर सिंह ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रशासन की दस अलग-अलग टीमें लगातार शहर के

विभिन्न हिस्सों में सर्वे और मैपिंग के कार्य में जुटी हुई हैं। इस विशेष प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शहर के हर क्षेत्र का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना है ताकि भविष्य में लोगों को अपनी प्रॉपर्टी और जमीन-जायदाद से संबंधित किसी भी

प्रकार के विवाद का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि इस डिजिटल मानचित्रण के तैयार होने के बाद न केवल आम जनता को कानूनी उलझनों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी और अधिक पारदर्शिता

आएगी और सरकार को विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट की प्रगति का विवरण देते हुए जिला नगर आयुक्त ने बताया कि शहर की कई कॉलोनियों में काम पहले से ही चल रहा है। इसी कड़ी में अब दस नई

कॉलोनियों और क्षेत्रों में भी सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के तहत कैलाश नगर नर्थ, एंजलीन कालोनी, आरती नगर, अग्रसेन कॉलोनियों, दया नगर, मोती नगर, केवय नगर, शास्त्री नगर, शिव कॉलोनी और

एचएसवीपी सेक्टर-एक में कार्य का आवंटन किया जा चुका है। अब प्रशासन ने इस चरण को बढ़ाते हुए कैलाश नगर साउथ, नर्सिग कालोनी, आरती नगर, अग्रसेन कॉलोनियों, दया नगर, मोती नगर, केवय नगर, शास्त्री नगर, शिव कॉलोनी और

सेक्टर-एक पार्ट एक व दो, केशव नगर एक्सटेंशन, शास्त्री नगर, शिव कॉलोनी पार्ट-एक और विलेज नसीबपुर हुडा सेक्टर के समीप बाहरी क्षेत्र) में भी नए सिर से आवंटन कर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

बेंगलुरु में खुला अमेज़न का एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस

12 मंजिला, 11 लाख वर्ग फुट का आधुनिक परिसर, एक साथ 7,000 कर्मचारी काम करेंगे

बेंगलुरु। अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज एमेज़न ने बेंगलुरु में अपना एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोलने की घोषणा की। नया परिसर 12 मंजिला और 11 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। यह केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित है और इसमें भारत में 7,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल और सहयोगी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अमेज़न ने भारत में अब तक 40

अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है और 2030 तक अतिरिक्त 35 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। कर्नाटक के लघु एवं मध्यम उद्योग एवं अवसंरचना विकास मंत्री एम.बी. पाटिल ने उद्घाटन के दौरान कहा कि इस निवेश से उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा होंगी, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा। नए परिसर को टीम सहयोग,

लचीलापन, सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कर्मचारियों के लिए बास्केटबॉल और पिक्लबॉल कोर्ट, एम्फीथिएटर, हरे-भरे लॉन और सामुदायिक बाहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैफेटेरिया दो मंजिलों पर फैला है और इसमें वैश्विक व्यंजनों की विस्तृत श्रृंखला परोसी जाती है। इस परियोजना में जिम्मेदार सामग्री स्रोत, कार्यालय संपत्तियों का पुनः उपयोग और उच्च दक्षता वाली प्रणालियां

शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह पहल अमेज़न की दीर्घकालिक सतत विकास रणनीति का हिस्सा है। अमेज़न इंडिया के एक ओ धिकारी के अनुसार, बेंगलुरु लंबे समय से कंपनी की तकनीकी और व्यावसायिक टीमों का घर रहा है और आज भी यह नवाचार और प्रतिभा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। नया ऑफिस कंपनी के भारत में निरंतर निवेश और विस्तार का प्रतीक है।

एपल ने भारत में पीएलआई योजना के तहत 2.5 लाख से अधिक नौकरियां दी



नौकरियों में 70 प्रतिशत से अधिक 19-24 वर्ष की महिलाएं शामिल

नई दिल्ली ।

ब्यूटिफिटन मुख्यालय वाली एपल इंक ने पिछले पांच वर्षों में भारत में 2,50,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। यह तेजी से बढ़ती संख्या मोबाइल-फोन विनिर्माण के लिए 2021 में शुरू हुई उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के कारण संभव हुई। खास बात यह है कि इन नौकरियों में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जिनमें कई की उम्र 19-24 वर्ष है और यह उनका पहला रोजगार अवसर है। आईफोन के दो मुख्य वेंडर, टाटा समूह और फॉक्सकॉन ने मिलकर लगभग 1,40,000 प्रत्यक्ष नौकरियां प्रदान की हैं, जो योजना के तहत प्रतिज्ञात 1,18,290 नौकरियों से अधिक है।

इसके अतिरिक्त 1,10,000 नौकरियां अन्य भारतीय, विदेशी और संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा दी गई हैं, जो मुख्य रूप से

एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी हैं और आईफोन से संबंधित उपकरणों का उत्पादन करती हैं। इन कंपनियों का नेटवर्क भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैला हुआ है। ये कंपनियां मुख्य रूप से आईफोन असंबली प्लांट को उपकरण और पुर्जें उपलब्ध कराती हैं, जबकि कुछ कंपनियां जैसे जाबिल और एक्स सीधे एपल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में योगदान देती हैं। टाटा समूह के तीन आईफोन प्लांट लगभग 72,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वहीं फॉक्सकॉन के दो कारखानों में 70,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। पीएलआई योजना के प्रभाव से मोबाइल निर्माण में औसत मासिक वेतन 11,000 से बढ़कर 18,000-20,000 रुपए हो गया। अकेले एपल और इसके सहयोगी नेटवर्क में अनुमानित 7,50,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न हुई हैं। भारत का स्मार्टफोन निर्यात 2025 में 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें आईफोन की हिस्सेदारी 23 अरब डॉलर रही।

एनएमपी 2.0 का 16.72 लाख करोड़ मुद्राकरण जुटाने का लक्ष्य

- योजना के तहत 2,000 से अधिक संपत्तियों में निजी भागीदारी लाई जाएगी



नई दिल्ली ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (एनएमपी 2.0) के दूसरे चरण का अनावरण करते हुए वित्त वर्ष 2026 से 2030 के बीच 16.72 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य घोषित किया। इस योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार के मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों की उत्पादक संपत्तियों के मुद्राकरण के माध्यम से पूंजी जुटाना है। सरकार का कहना है कि इससे नई अवसंरचना परियोजनाओं और पूंजीगत व्यय के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे, बिना राजकोषीय बोझ बढ़ाए।

नीति आयोग के एक वे रिष्ठ अे धिकारी के अनुसार एनएमपी 2.0 में राजमार्ग, बिजली, बंदरगाह और रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। योजना के तहत 2,000 से अधिक संपत्तियों में निजी भागीदारी लाई जाएगी। कुल लक्ष्य का एक-चौथाई से अधिक हिस्सा

राजमार्ग क्षेत्र से आने की उम्मीद है, जबकि बंदरगाह, कोयला और खनिज क्षेत्रों से भी महत्वपूर्ण योगदान संभावित है। इस चरण में पहली बार पांच वर्षों के दौरान 5.8 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश का अनुमान जोड़ा गया है। वित्त वर्ष 2026 में 2.49 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, हालांकि वास्तविक प्राप्ति 2 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

योजना में अस्थायी संपत्ति हस्तांतरण, सूचीबद्ध कंपनियों में हिस्सेदारी का विनिवेश और नकद प्रवाह का प्रतिभूतिकरण जैसे उपाय शामिल हैं। रेलवे को 2.62 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें सात सूचीबद्ध रेलवे पीएएसयू में सरकारी हिस्सेदारी घटाकर 83,700 करोड़ रुपये जुटाने का प्रावधान है। सरकार को उम्मीद है कि एनएमपी 2.0 से बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी।

पीएम सूर्य घर योजना 30 लाख घरों में रूफटॉप सौर इकाई स्थापित

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत फरवरी 2024 से अब तक देशभर में 30 लाख से अधिक घरों की छतों पर सौर ऊर्जा इकाई लगाई जा चुकी है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने यह जानकारी दी।

जोशी ने बताया कि जब एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित हो जाएंगे, तो अनुमानित 1,000 अरब यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन संभव होगा।

इन इकाइयों के 25 साल के जीवनकाल में लगभग 72 करोड़ टन कार्बन डिऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है। मंत्री ने कहा कि यह योजना घरेलू बिजली बिल कम करने के साथ-साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरित परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2026-27 तक देशभर में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर इकाई स्थापित करना है, जिससे टिकाऊ ऊर्जा और



पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

बायजूज़ अरबों डॉलर के वैल्यूएशन से कानूनी और वित्तीय संकट तक

- ऑनलाइन शिक्षा की मांग में गिरावट और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से हुआ नुकसान

नई दिल्ली ।

भारत की प्रमुख एड-टेक कंपनी बायजूज़ कभी 22 अरब डॉलर (लगभग 1.98 लाख करोड़ रुपये) के वैल्यूएशन तक पहुंची थी। कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की

बढ़ती मांग ने कंपनी को तेजी से बढ़ने का अवसर दिया। बायजूज़ ने वैश्विक विस्तार, बड़े अधिग्रहण और ब्रांडिंग में भारी निवेश किया। महामारी के बाद फंडिंग सस्ती नहीं रही और निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ। ऑनलाइन शिक्षा की मांग में गिरावट और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने कंपनी की आय को प्रभावित किया। नवंबर 2021 में लिया गया 1.2 अरब डॉलर का टर्म लोन बायजूज़ के लिए चुनौती बन गया। तिमाही ब्याज भुगतान (330 करोड़ रुपए) में चूक के बाद विदेशी लेंडर्स ने अमेरिका में मुकदमा दायर किया। प्रवर्तन

निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कंपनी के दफ्तरों पर छापे मारे और लगभग 9,362 करोड़ रुपए के कथित उल्लंघन का नोटिस जारी किया। इसके अलावा बायजूज़ और लेंडर्स के बीच समय से पहले भुगतान और कानूनी कार्रवाई को लेकर भी विवाद चल रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि 533 मिलियन डॉलर का फंड गायब है, जिससे कंपनी पर विवाद और बढ़ गया है। महामारी के समय में किए गए आक्रामक विस्तार और निवेश की रणनीति अब बायजूज़ के लिए बोझ साबित हो रही है।

रुपया गिरावट के साथ बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मंगलवार को 4 पैसे कि गिरावट के साथ ही 90.93 पर बंद हुआ आज सुबह कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिकी डॉलर के मजबूत रुख से रुपया शुरुआती कारोबार में सात पैसे नीचे आकर 90.96 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार भरेलू शेयर बाजारों की खराब शुरुआत से स्थानीय मुद्रा पर और दबाव डाला, हालांकि विदेशी निवेशकों के निवेश ने इसे सहारा दिया एवं तेज गिरावट को रोक दिया। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.91 पर खुला। फिर टूटकर 90.96 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से सात पैसे की गिरावट दिखाता है। रुपया सोमवार को पांच पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.89 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 फीसदी की बढ़त के साथ 97.81 पर रहा।



मोवसी पावर ने तमिलनाडु में 558 मेगावाट बिजली आपूर्ति का ठेका हासिल किया

- बिजली आपूर्ति 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी

नई दिल्ली ।

अदाणी पावर की सहायक कंपनी मोवसी पावर को ते मिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन से पांच वर्षों के लिए 558 मेगावाट बिजली आपूर्ति का ठेका मिला है।

कंपनी ने बोली में 5,910 रुपये प्रति यूनिट का सबसे प्रतिस्पर्धी शुल्क प्रस्तावित कर ठेका जीता। यह आपूर्ति 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। मोवसी पावर तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 1,200 मेगावाट क्षमता का संयंत्र संचालित करता है। अदाणी पावर भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली उत्पादक कंपनी है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 18.15 गीगावाट है। संयंत्र की दोनों इकाइयों के पास बिजली आपूर्ति समझौते हैं, जिससे संचालन और राजस्व में स्थिरता बनी रहती है। अदाणी पावर की परिचालन क्षमता का 95 फीसदी से अधिक हिस्सा मध्यम से दीर्घकालिक अनुबंधों के तहत सुरक्षित है। कंपनी का लक्ष्य आने वाले वर्ष तक सभी परिचालित और जल्द चालू होने वाले संयंत्रों के लिए लगभग 100 फीसदी पीपीए हासिल करना है। यह रणनीति अल्पकालिक बाजार अस्थिरता के जोखिम को कम करती है और दीर्घकालिक राजस्व की स्पष्टता प्रदान करती है। इस ठेके से तमिलनाडु के उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध होगी। ग्रिड की स्थिरता मजबूत होगी और घरों, उद्योगों एवं व्यवसायों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। प्रतिस्पर्धी शुल्क पर बिजली उपलब्ध होने से उपभोक्ताओं को कतिफायती और भरोसेमंद ऊर्जा का लाभ मिलेगा।



बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार; सेंसेक्स 1068 अंक टूटा, निफ्टी 25500 के नीचे

छह लाख करोड़ से अधिक का नुकसान

नई दिल्ली ।

भारतीय बाजार मंगलवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1068.74 अंक या 1.28 प्रतिशत गिरकर 82,225.92 पर बंद हुआ। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 288.35 अंक या 1.12 प्रतिशत गिरकर 25,424.65 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव व्यापक रहा, जिसमें मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक में करीब 1 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। तेज गिरावट के बीच निवेशकों की संपत्ति में भारी कमी आई। इससे निवेशकों को एक ही दिन में छह लाख करोड़ रुपये से



अधिक का नुकसान हुआ। एआई के संभावित प्रभाव के कारण तकनीकी शेयरों में कमजोरी का रुझान जारी है। भारतीय आईटी कंपनियों के एडीआर में कमजोरी यह संकेत देती है कि यह सेगमेंट दबाव में बना रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का आज बाद में होने वाला स्टेट

ऑफ द यूनिन संबोधन और उसमें दिया जाने वाला संदेश वैश्विक बाजारों द्वारा उत्सुकता से देखा जाएगा। इन कारणों से दिखी गिरावट वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर अनिश्चितता के बीच निवेशकों का मनोबल कमजोर बना रहा। यह

कमजोरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 10-15 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ ढांचे की घोषणा के बाद टैरिफ संबंधी चिंताओं के फिर से उभरने से उत्पन्न हुई है, जिससे वैश्विक आर्थिक विकास और कंपनियों की आय पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं।

ईपीएफओ निष्क्रिय खातों में फंसे 30.52 करोड़ जल्द लौटाएगी

- 31.86 लाख निष्क्रिय खातों को बंद करने की बड़ी योजना

नई दिल्ली ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 7.11 लाख निष्क्रिय खातों में फंसे 30.52 करोड़ रुपये जल्द खाताधारकों या उनके कानूनी वारिसों को लौटाने का फैसला किया है। यह पहल 31.86 लाख निष्क्रिय खातों को बंद करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। मंत्रालय के अनुसार, इनमें कुछ खाते 20 साल से पुराने हैं और पिछले तीन साल से इनमें कोई लेनदेन नहीं हुआ है। श्रम मंत्रालय ने इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें ऐसे खातों

को चुना गया है जिनमें 0 से 1,000 रुपये तक की राशि है और जो आधार से जुड़े हैं। ईपीएफओ सीधे इन खातों में पैसे सीधे सफर करेगा। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर बाकी निष्क्रिय खातों में भी इसी तरह राशि लौटाई जाएगी। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पीएफ एक अनिवार्य सरकारी योजना है। इसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12 फीसदी योगदान करते हैं, जबकि नियोजक भी उतना ही योगदान करता है। यदि किसी खाते में तीन साल तक कोई लेनदेन नहीं होता तो उसे निष्क्रिय घोषित किया जाता है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईपीएफओ सदस्य अपना पैसा आसानी से निकाल सकें। हालांकि, छोटे-छोटे निष्क्रिय खातों में फंसी राशि प्रशासनिक



जिम्मेदारियों और वित्तीय जवाबदेही में चुनौती पैदा करती है। हजारों करोड़ रुपये ऐसे निष्क्रिय खातों में फंसे हुए हैं क्योंकि लोग काम राशि निकालने के लिए आने-जाने की झंझट में बचते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर, ईपीएफओ धीरे-धीरे बाकी निष्क्रिय खातों में भी यह प्रक्रिया लागू करेगा। इससे खाताधारकों का पैसा सुरक्षित तरीके से लौटाया जाएगा और निष्क्रिय खातों का बोझ भी कम होगा।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन 1,500 एवसपर्ट्स की करेगा नियुक्ति

- लगभग 40 फीसदी पद सविदा या लचीले आधार पर होंगे

नई दिल्ली ।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) अब केवल कारखानों के निरीक्षण तक सीमित नहीं रहेगा। संगठन ने 1,500 वैज्ञानिक और विशेषज्ञों को नियुक्त करने की योजना बनाई है। ये विशेषज्ञ क्लिनिकल रिसर्च, बायोलॉजिकल, सांख्यिकी, इंजीनियरिंग और नियामकीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करेंगे। इनमें से लगभग 40 फीसदी पद सविदा या लचीले आधार पर होंगे। इस कदम का उद्देश्य दवा मंजूरी और निगरानी प्रक्रिया को वैज्ञानिक, तेज और प्रभावी बनाना है। सीडीएससीओ ने जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रक्रिया को तेज कर दिया है। निरीक्षण में उत्पाद की जोखिम स्थिति, पिछली अनुपालन स्थिति और खुफिया सूचनाओं को ध्यान में रखा जाता है। 2022 के अंत से अब तक 1,250 विनिर्माण इकाइयों का ऑडिट किया जा चुका है। स्ट्राफ की कमी के कारण अब निरीक्षण में अधिसूचित थर्ड-पार्टी एजेंसियों को शामिल किया जाएगा। इससे निगरानी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। कफ सिरप निर्माण क्षेत्र बार-बार गुणवत्ता समस्याओं का केंद्र रहा है। देश में 1,300 कफ सिरप निर्माता हैं, जिनमें से लगभग 1,100 इकाइयों का निरीक्षण हो चुका है। गंभीर कमियों वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कुछ को बंद करने का निर्णय लिया गया।

आरबीआई ने जारी किया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के प्रीमियर रिडेम्पशन कैलेंडर

अगले 6 महीने में 33 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गुना सकेंगे निवेशक

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) के समय से पहले रिडेम्पशन के लिए कैलेंडर जारी किया। यह सुविधा उन बॉन्ड पर लागू होगी जिनकी रिडेम्पशन तारीख 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच है। निवेशक 22 अक्टूबर 2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार, जारी होने की तारीख से 5 साल पूरे होने पर एसजीबी समय से पहले गुना सकते हैं। आरबीआई के शेड्यूल के अनुसार 2018-19 से 2021-22 तक जारी 33 ट्रांच इस छह महीने की अवधि में प्रीमियर रिडेम्पशन के लिए पात्र हैं। सबसे पहला ट्रांच 2018-19 सीरीज-2 है, जो 23 अप्रैल 2026 से गुनाई के लिए खुला रहेगा। आवेदन विंडो 23 मार्च से 13 अप्रैल 2026 तक रहेगी। आखिरी पात्र ट्रांच 2019-20 सीरीज-10 है, जिसकी रिडेम्पशन 11 सितंबर 2026 होगी और आवेदन 11 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक होगा। निवेशक आरबीआई के अधिकृत कार्यालयों, डिवाइजिटी या आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म का माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि अप्रत्याशित अवकाश पर तारीखों में बदलाव हो सकता है। निवेशकों को अपनी ट्रांच की सटीक आवेदन अवधि पर ध्यान देना जरूरी है।



मुफ्त रेवड़ी संस्कृति जीवंत लोकतंत्र के लिये घातक



मा रतीय लोकतंत्र की विडंबना यह है कि चुनाव आते ही जनसेवा का स्वरूप बदलकर जनलुभावन राजनीति में परिवर्तित हो जाता है। राजनीतिक दलों ने मुफ्त की योजनाओं को चुनावी सफलता का शॉर्टकट बना लिया है। मतदाताओं को तात्कालिक आर्थिक लाभ देकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति लगातार मजबूत हो रही है। आगामी तीन-चार माह में विधानसभा चुनाव होने है, इसी संदर्भ में जब असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक सरगमियां तेज हुईं, तब इस संस्कृति का प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसी पृष्ठभूमि में देश की शीर्ष अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, ने मुफ्त की योजनाओं के अनियंत्रित विस्तार पर गंभीर टिप्पणी की। यह टिप्पणी केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को लेकर एक चेतावनी है।

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं। लेकिन जब जनहित और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समस्या जन्म लेती है। लक्षित समर्थन और अतिरेक उदारता में अंतर है। एक ओर ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, दूसरी ओर ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल मतदाता को तात्कालिक राहत देकर उसे निर्भरता की आदत सिखाती हैं। जब राजस्व घाटे से जुड़ा रहे राज्य मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा या नकद वितरण की घोषणाएं करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि यह संसाधन कहाँ से आएंगे और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? राजकोषीय अनुशासन किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत का आधार है। यदि राज्य अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए खजाने को खाली करता है, तो दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। जो धन बुनियादी ढांचे के निर्माण, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण, विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार और रोजगार सृजन में लगाना चाहिए, वह वोटों की फसल काटने में खर्च हो जाता है। यह प्रवृत्ति केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी चिंताजनक है। लोकतंत्र में मतदाता की स्वतंत्रता सर्वोपरि मानी जाती है। यदि मतदाता को परोक्ष रूप से आर्थिक प्रलोभन देकर प्रभावित किया जाता है, तो यह स्वतंत्र निर्णय की भावना को कमजोर करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने तार्किक प्रश्न उठाया कि राज्य रोजगार सृजन और कौशल विकास पर अधिक ध्यान क्यों नहीं देते? वास्तव में रोजगार ही स्थायी सशक्तीकरण का माध्यम है। जब व्यक्ति अपने श्रम और कौशल से आय अर्जित करता

है, तब उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं। इसके विपरीत, निरंतर मुफ्त सुविधाएं व्यक्ति को निर्भर बनाती हैं। धीरे-धीरे परिश्रम की संस्कृति कमजोर पड़ती है और समाज में अकर्मण्यता की मानसिकता नपनपने लगती है। यह स्थिति लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सक्रिय और जिम्मेदार नागरिकता का नाम है। चुनाव पूर्व घोषित योजनाओं की निष्पक्षता भी प्रश्नों के घेरे में है। जब आचार संहिता लागू रहने के दौरान बड़े पैमाने पर आर्थिक वितरण होता है, तो विपक्षी दल इसे असमान प्रतिस्पर्धा मानते हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष निगरानी की जिम्मेदारी भारत का निर्वाचन आयोग पर आती है। निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी दल मतदाताओं को अप्रत्यक्ष रिश्वत देकर चुनावी लाभ न ले। आचार संहिता का उल्लंघन केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन है। यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो भविष्य में यह प्रवृत्ति और गहरी जड़ें जमा सकती है। निस्संदेह, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि राज्यों का यह प्रार्थमिक कर्तव्य है कि वे विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की खास तौर से देखभाल करें। हालाँकि, जब राजस्व घाटे वाले राज्य मुफ्त की योजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, तो सरकारी खजाने पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है। विडंबना यह है कि जिस धराशायि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं को

सक्षम बनाने और शिक्षा की सुविधा को समृद्ध करने के लिये किया जाना चाहिए, वो राशि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये खर्च कर दी जाती है। जरूरत इस बात की है कि कौशल विकास के जरिये लोगों को इस तरह सक्षम बनाया जाए जिससे उन्हें दीर्घकालिक व स्थायी लाभ मिल सकें। यह भी समझना होगा कि मुफ्त योजनाओं का हर स्वरूप गलत नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में राहत देना, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय सहायता पहुंचाना, सामाजिक न्याय के तहत वंचित वर्गों को अवसर देना-ये सब राज्य की जिम्मेदारी है। परंतु चुनावी मौसम में अचानक घोषणाओं की बाढ़ आ जाना और दीर्घकालिक वित्तीय परिणामों की अनदेखी करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत नहीं है। यह राजनीतिक दलों के वैचारिक दिवालियेपन को दर्शाता है, जहां दूरदृष्टि की जगह तात्कालिक लाभ को प्रार्थमिकता दी जाती है। लोकतंत्र की मजबूती केवल संस्थाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों की सजगता से भी आती है। यदि मतदाता केवल तात्कालिक लाभ देखकर मतदान करता है, तो वह अनजाने में ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करता है जो अंततः उसी के भविष्य को प्रभावित करती है। परिपक्व मतदाता वही है जो घोषणाओं के पीछे की मंशा और आर्थिक व्यवहार्यता को समझे। वह यह पृष्ठ कि पांच साल बाद राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, विकास की दिशा क्या होगी और रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे। लोकतंत्र में वोट केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है।

आज भारत स्वयं को वैश्विक मंच पर एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। हम विश्वगुरु बनने का संकल्प लेते हैं, लेकिन यदि हमारी राजनीति लोकलुभावनवाद के जाल में उलझी रहेगी, तो यह संकल्प खोखला सिद्ध होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव तभी सार्थक है जब हमारी नीतियां दूरदर्शी, संतुलित और टिकाऊ हों। मुफ्त की संस्कृति से बाहर निकलकर उत्पादकता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। यह समय आत्ममंथन का है। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि जनता को सशक्त बनाना केवल धन बांटने से संभव नहीं है। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार-ये चार स्तंभ किसी भी राष्ट्र की मजबूती तय करते हैं। यदि इन पर निवेश बढ़ेगा, तो नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे और राज्य पर बोझ कम होगा। वहीं, नागरिकों को भी यह ठानना होगा कि वे तात्कालिक प्रलोभनों के बजाय दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देंगे। लोकतंत्र की सुदृढ़ता तभी सुनिश्चित होगी जब शासन और जनता दोनों अपने-अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें।

निस्संदेह, चुनावी निष्पक्षता के लिये यह आवश्यक हो गया है कि चुनाव से पहले घोषित की गई या लागू की गई लोकलुभावन नीतियों व योजनाओं की गहन पड़ताल की जाए। विपक्षी दलों द्वारा बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया था कि पिछले साल अक्तूबर में आचार संहिता लागू रहने के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 15,600 करोड़ रुपये दिए गए थे। जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध कदम था। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपरोक्ष रूप से रिश्वत देने के प्रयासों पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही इस दिशा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में कार्रवाई भी करना चाहिए। निर्विवाद रूप से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना हमारे जीवंत लोकतंत्र के लिये हानिकारक है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। यह कार्य करने की मानसिकता को बाधित करती है और समाज में सरकार-निर्भरता एवं अकर्मण्यता की संस्कृति को जन्म देती है। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो आर्थिक असंतुलन और राजनीतिक अविश्वास दोनों बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि नीतियों की पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और चुनावी निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यही लोकतंत्र की वास्तविक रक्षा है, यही राष्ट्र के उज्वल भविष्य की आधारशिला है।

संपादकीय

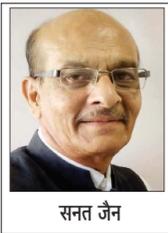
शंकराचार्य बनाम साधु

तिथ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्रार्थमिकी दर्ज की गई है। आरोप अश्लील हैं कि उन्होंने और उनके शिष्य ने दो नाबालिग शिष्यों का यौन शोषण किया। जो आशुतोष ब्रह्मचारी नामक कथित साधु ने अदालत में शिकायत दर्ज की थी, वह भी एक और सन्यासी, कथित जगद्गुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बताया जा रहा है। अदालत में जज के सामने धारा 164 के तहत नाबालिग शोषितों के बयान भी दर्ज करा दिए गए हैं। पाँक्सो की विशेष अदालत ने प्रार्थमिकी दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। चूँकि मामला पाँक्सो का है, लिहाजा बेहद संवेदनशील है। क्या शंकराचार्य को जेल भी भेजा जा सकता है? यदि ऐसा हुआ, तो बड़ा धार्मिक वज्रपात होगा, क्योंकि शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि सनातन के शिखर-पुरुष हैं, सर्वोच्च धर्मगुरुओं में शामिल हैं। जिस साधु-संत के असंख्य श्रद्धालु हैं, उग्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोदी जिन्हें ह्यभगवानह्म मान कर प्रणाम करते हैं, एक और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, शंकराचार्य के ही, बटुकों की शिक्षा खींचने को ह्यमहापाह्म करार देते हैं और अपने आवास पर बटुकों का सम्मान करते हैं, उसी शख्स के शंकराचार्य होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए थे। आश्चर्य है कि उग्र में यह क्या हो रहा है? हिंदुत्व और सनातन की कट्टर समर्थक, पैरोकार भाजपा की सरकार में सनातन-पुरुष पर ही घमासान क्यों मचा है? जो अभी तक शंकराचार्य हैं, जिनके पदनाम पर सर्वोच्च अदालत ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है, जो शंकराचार्य सनातन के शिखर संतों में एक हैं और आदि शंकराचार्य की प्रतिमूर्ति हैं, उन्हें ही दुराचारी और बलात्कारी करार क्यों दिया जा रहा है? इन आरोपों की तुलना आसाराम बापू के केस से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें बलात्कार की निरंतर पीड़िता नाबालिग कन्या के परिजनों ने भी शिकायतें दर्ज कराई थीं। मीडिया के सामने आकर दुष्कर्म-कथा सुनाई थी। आसाराम को ह्यभगवानह्म मानने वालों की भी कमी नहीं थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक उनके ह्यभक्त थे। मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की आस्था, श्रद्धा भी उनके प्रति थी। आसाराम कई सालों से जेल में हैं। बीते दिनों स्वास्थ्य आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी।

चिंतन-मनन

कहीं आप भी पाप की पूंजी तो जमा नहीं कर रहे

क्या आपने कभी किसी के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठायी है। किसी कमजोर और लाचार को पीटता देखकर मदद के लिए आगे आए हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो समझ लीजिए आपने अपने खाते में पाप की पूंजी जमा कर ली है। जिस प्रकार से पाप और पुण्य को परिभाषित किया गया है उसके अनुसार जो व्यक्ति किसी को कष्ट में देखकर उसकी मदद नहीं करता है। किसी के भय से अथवा अपने स्वार्थ के कारण झूठ बोलता है और शरण में आये व्यक्ति की रक्षा नहीं करता है वह पापी है। इस संदर्भ में एक कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। एक थे राजा शिवि। इनके धार्मिक स्वभाव और दयालुता एवं परोपकार के गुण की ख्याति स्वर्ग में भी पहुंच गयी। इन्द्र और अग्नि देव ने योजना बनायी कि राशि शिवि के गुणों को परखा जाए। एक दिन अग्नि देव कबूतर बने और इन्द्र बाज। कबूतर उड़ता हुआ राजा शिवि की गोद में आकर बैठ गया और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। इसी बीच बड़ा सा बाज राजा शिवि के पास पहुंचा और कबूतर को वापस करने के मांग करने लगा। बाज ने कहा कि, कबूतर मेरा आहार है अगर आप मुझे वापस नहीं करोगे तो आपको मुझे भूखा रखने का पाप लगेगा। बाज की बातों को सुनकर राजा शिवि ने कहा कि कबूतर मैं तुम्हें नहीं दूंगा अगर कोई अन्य उपाय है तो बताओ। बाज ने कहा कि कबूतर के मांस के बराबर मुझे मांस दे दीजिए इससे मेरा काम हो जाएगा। राजा ने विचार किया कि एक जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव का कष्ट देना पाप होगा। यही सोच कर राजा ने कबूतर को तराजू के एक पलड़े में डाल दिया और अपने शरीर से मांस काटकर दूसरे पलड़े में रखने लगे। लेकिन कबूतर का मांस रखने के बाद भी पलड़ा हिला तक नहीं। अंत में राजा शिवि स्वयं दूसरे पलड़े पर बैठ गये और बाज से कहा कि तुम मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लो। राजा के इस दयालुता और शरण में आये हुए कि मदद करने की भावना को देखकर कबूतर अग्नि देव और बाज देवराज इन्द्र के रूप में प्रकट हुए। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। देवराज इन्द्र ने कहा कि तुम ने धर्म की लाज रखी है। जो शरण में आये की रक्षा नहीं करता वह पापी है। कमजोर की सहायता न करने वाला भी अधर्मी है। दोनों देवताओं ने राजा शिवि को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग चले गये।



सनत जैन

मे किसको में कुख्यात ड्रग सरगना नेमेसियो ओसेगेरा सवातिस उर्फ 'एल मेचो' के मारे जाने की खबर के बाद हुई भारी हिंसा से मेक्सिको को अनिश्चितता के दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। आम जनता संडकों पर उतरकर प्रदर्शन करती नजर आई है। नशे के कारोबार में (सीजेएनजी) प्रमुख के रूप में ड्रग लॉर्ड को न केवल मेक्सिको, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का केंद्रीय चेहरा माना जाता था। मेक्सिको की सरकार इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। किंतु ड्रग सरगना के मारे जाने के तुरंत बाद भड़की आगजनी, हाईवे जाम और सुरक्षा कर्मियों पर हमले से यह सवाल उठता है, क्या किसी सरगना के मारे जाने पर जनता का विद्रोह इस रूप में देखने को मिल सकता है? एल मेचो पर अमेरिका की सरकार ने बड़ा इनाम घोषित किया था। डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल से ही मेक्सिको पर ड्रग



सुनील कुमार महला

मे स कचरे का प्रबंधन आज के समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुका है। कहन गलत नहीं होगा कि आज लगातार बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण धरती पर ठोस कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिससे हमारे पर्यावरण, परिस्थितिकी तंत्र, मानव व जीवों के स्वास्थ्य और विभिन्न संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यदि इस कचरे का सही तरीके से संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण(रि-साइक्लिंग) और इसका समय रहते निपटान नहीं किया गया, तो नीले ग्रह(धरती पर) पर भूमि, जल और वायु प्रदूषण की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। वास्तव में, आज के समय में ठोस कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करना, जैविक कचरे से खाद बनाना, प्लास्टिक और अन्य पदार्थों का पुनर्चक्रण(रि-साइक्लिंग) करना तथा जन-जागरूकता बढ़ाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए ठोस कचरे का प्रभावी प्रबंधन केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जब समाज और प्रशासन मिलकर प्रयास करेंगे, तभी सतत विकास(सस्टेनेबल डेवलपमेंट) और स्वच्छ पर्यावरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता च्लू कि इस क्रम में

कार्टेल के खिलाफ जंग और मेक्सिको की अग्निपरीक्षा

तस्करी के खिलाफ कठोर कार्रवाई का दबाव अमेरिका की सरकार बनाती रही है। फेडरल संकट ने अमेरिका की आंतरिक राजनीति को झकझोर दिया है, इसका प्रभाव द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ना तय है। मेक्सिको की हिंसा केवल आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसका असर अमेरिका सहित अन्य देशों पर भी पड़ना तय है। यह घटना भू-राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ी दिखती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यह मेक्सिको की संप्रभु रणनीति का हिस्सा है, या अमेरिकी दबाव का परिणाम है। इतिहास बताता है कि कार्टेल के शीर्ष नेता को मार देने से इस समस्या का हल नहीं होता है। इससे ड्रग के कारोबार, राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों में स्थिरता संभव नहीं है। 2016 में जोकिवन एल चापो गुजमान की गिरफ्तारी के बाद भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। आम जनता और सत्ता के बीच संघर्ष बढ़ा था। संगठित अपराध का नेटवर्क समानांतर व्यवस्था की तरह संचालित होता है। एक चेहरा हटता है, तो उसके कई दावेदार उभरते हैं। गैंग में वर्चस्व की लड़ाई आम नागरिकों की सुरक्षा और जीवन यापन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती है। एल मेचो की मौत के बाद इस तरह की घटनाएं इसी आशंका को पुष्ट कर रही हैं। ड्रग कारोबार और राजनीतिक संरक्षण का मूल मेक्सिको, अमेरिका एवं कई अन्य देशों तक फैला हुआ है। दशकों से मेक्सिको में फैली गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक संघर्ष, भ्रष्टाचार और कमजोर तथा भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्था से जुड़ता है।

मेक्सिको के सीमावर्ती इलाकों में प्रशासनिक पकड़ हमेशा से कमजोर रही है। नशे के कारोबारी और इससे जुड़े हुए लोगों की समानांतर सत्ता चलती है। नशे के कारोबार में लगे अपराधी तत्व जिस तरह से काम करते हैं, उससे स्थानीय कारोबारियों को वसूली के उर से नियंत्रण और सीमापार तस्करी इनके साधन हैं। ऐसे में सैन्य कार्रवाई समाधान नहीं हो सकती है। मेक्सिको सरकार के लिए यह दोहरी चुनौती है। एक ओर सरकार के ऊपर तत्काल कानून-व्यवस्था बहाल कर नागरिकों में भरोसा कायम करना है, दूसरी ओर दीर्घकालिक सुधारों पर गंभीरता से काम करना होगा। मेक्सिको में न्यायिक पारदर्शिता, गवाहों की सुरक्षा, नशे की कारोबार में नेटवर्क पर वित्तीय प्रहार और पुलिस सुधार अनिवार्य है। सरकार, पुलिस और प्रशासन के बीच का भ्रष्टाचार रोकना, संस्थागत ढांचे को मजबूत नहीं किया तो यह 'जीत' अस्थायी साबित होगी। इसके साथ ही, इसका असर अमेरिका में भी पड़ना तय है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। जब तक अमेरिका में नशीली दवाओं की मांग बनी रहेगी, आपूर्ति के नए रास्ते और नए गिरोह समय-समय पर उभरते रहेंगे। नशे का कारोबार केवल मेक्सिको की समस्या नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय समस्या है। इससे निपटने के लिए साझा जिम्मेदारी जरूरी है। दबाव की नीति के बजाय सहयोग, खुफिया साझेदारी और सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा। एल मेचो का अंत



प्रतीकात्मक जीत हो सकती है, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। यदि मेक्सिको में सुशासन और पारदर्शिता चाहिए तो भुखमरी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सामाजिक निवेश की ठोस रणनीति बनानी होगी। तभी नशे के कारोबार के गैंगस्टर्स को छुआया से मेक्सिको बाहर निकल पाएगा। इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं करता है। नशे के कारोबार का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है, इसमें भारी पैसा है। इस नेटवर्क को इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से अभी कार्रवाई की गई है। कार्यवाही के पश्चात जिस तरह के हालात मेक्सिको के बन गए हैं, उस चुनौती से निपटना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका इस मामले में मेक्सिको को क्या मदद करता है, यह भी देखना होगा।

कचरे पर कड़ा रुख: न्यायपालिका के निर्देश और जमीनी सच्चाई



हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के ठीक से पालन न होने पर चिंता जताई है और 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए कई निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि साफ और स्वस्थ पर्यावरण में जीना, जीवन के अधिकार का ही अहम हिस्सा है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने 19 फरवरी को यह आदेश सुनाया। दरअसल, यह मामला भोपाल नगर निगम की उन अपीलों से जुड़ा था, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं। अदालत ने यह बात कही है कि अभी कानून में सुधार का इंतजार करना ठीक नहीं है, क्योंकि कचरे की खराब व्यवस्था से लोगों के स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ता है। कोर्ट ने माना कि पूरे देश में कचरा प्रबंधन नियमों का पालन समान रूप से नहीं हो रहा है और घरों से गीला-सूखा-खरबराक

कचरा अलग-अलग करने की व्यवस्था अभी तक भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। बड़े शहरों में बढ़ते कचरे के ढेर भी चिंता का कारण हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा अहम नहीं तो कभी नहीं और स्पष्ट किया कि अगर श्रोत पर कचरा अलग नहीं होगा और जरूरी सुविधाएं नहीं होंगी, तो अच्छे परिणाम की उम्मीद करना व्यर्थ है। अदालत ने पार्षदों, महापौरों और वार्ड प्रतिनिधियों को कचरा अलग कराने के लिए जिम्मेदार लीड फैसिलिटेटर बनाने को कहा, ताकि हर नागरिक नियमों का पालन करे। यहां पाठकों को बताता च्लू कि लीड फैसिलिटेटर वह व्यक्ति होता है जो किसी कार्यक्रम, प्रशिक्षण, कार्यशाला या परियोजना में पूरे समूह की प्रक्रिया को नेतृत्व करता है और यह सुनिश्चित करता है कि गतिविधियाँ सही दिशा में और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार चलें। अच्छी बात यह है कि सभी नगर निकायों को 100% पालन के लिए समय-सीमा तय कर सार्वजनिक करने, प्रगति की फोटो

जिलाधिकारी को भेजने और बड़े कचरा उत्पादकों से 31 मार्च तक नियमों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को चार तरह के कचरे (गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष) के अलग-अलग प्रबंधन की व्यवस्था जल्दी तैयार करने को कहा गया है। अदालत ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया कि कचरा प्रबंधन नियमों को स्कूल की पढ़ाई में शामिल किया जाए और इन्हें सभी राज्यों की स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाए। अब नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। पहले जुरामां, बार-बार उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर आपराधिक केस भी दर्ज किया जा सकता है। लापरवाही करने वाले अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे। कोर्ट ने मोबाइल अदालतों की संभावना पर भी विचार करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल 2026 से देश के सभी न्यायालयों और संस्थानों में भी कचरा प्रबंधन नियमों का पालन होना चाहिए। नगर निकायों को लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाने होंगे, जैसे कचरा कम करना, घर में खाद बनाना और सैनिटरी कचरे को सुरक्षित तरीके से पैक करना। ये सभी निर्देश इसलिए दिए गए हैं ताकि 1 अप्रैल 2026 से पहले पूरी तैयारी हो सके और नियम सही तरीके से लागू किए जा सकें। अंत में यही कहना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही चिंता जताई है कि ठोस कचरा प्रबंधन केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि जन-स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। नियमों के कमजोर अनुपालन, स्थानीय निकायों की जवाबदेही की कमी और योजनाओं जैसे अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा स्मार्ट सिटीज मिशन में खामियों के कारण समस्या बढ़ी है। समाधान के लिए सख्त नियम लागू करना, जनजागरण, अधिकारियों की जवाबदेही और बेहतर शहरी अवसंरचना निवेश अनिवार्य हैं, तभी कचरा-मुक्त भारत का लक्ष्य संभव हो पाएगा।

संक्षिप्त समाचार

कैलिफोर्निया हिमस्खलन में नौ स्कीयरों के शव बरामद

सिएरा, एजेंसी। कैलिफोर्निया की सिएरा नेवादा पर्वतमाला में आए भीषण हिमस्खलन के बाद बचाव दलों ने नौ बैककट्टी स्कीयरों के शव बरामद कर लिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, हादसा लोक ताही के पास केसल पीक क्षेत्र में हुआ था। नेवादा काउंटी शेरिफ शैनन मून ने बताया कि कई एजेंसियों और 42 स्वयंसेवकों की मदद से अभियान पूरा किया गया। मृतकों में ब्लैबर्न माउंटेन कंपनी के तीन गाइड, एंड्रयू अलिस्त्राटोस (34), निकोल चू (42) और माइकल हेनरी (30) शामिल हैं।

रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमले की कोशिश, 11 ड्रोन मारे

मॉस्को, एजेंसी। रूस की राजधानी मॉस्को पर रविवार को ड्रोन हमले की कोशिश की गई। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक घंटे के भीतर 11 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इसके बाद सुरक्षा कारणों से मॉस्को के चारों अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। रूसी सिविल एविएशन एजेंसी ने बताया कि डोमोडेदोवो, वुकोवो, झुकोव्स्की और शेरमेरेवो एयरपोर्ट अस्थायी तौर पर बंद किए गए हैं। अगली सूचना तक उड़ानों की आवाजाही रोक दी गई है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि एयर डिफेंस ने मॉस्को की ओर बढ़ रहे एक और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। इसके साथ ही गिराए गए ड्रोन की कुल संख्या 11 हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लगभग चार साल पूरे होने वाले हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन उसके विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर राजधानी मॉस्को, पर ड्रोन हमले करता है। वहीं रूस भी यूक्रेन पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है।

जापान के सम्राट ने 3/11 आपदा पीड़ितों की पीड़ा पर जताई चिंता

टोक्यो, एजेंसी। जापान के सम्राट नरुहितो ने अपने 66वें जन्मदिन के अवसर पर 2011 के भूकंप, सुनामी और परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों के जखम अब तक नहीं भरने पर चिंता व्यक्त की। 11 मार्च की बरसी से कुछ सप्ताह पहले जारी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अभी अधूरी है। सम्राट नरुहितो ने पिछले सप्ताह दिए गए अपने संदेश में कहा, 'बुनियादी ढांचे की बहाली में प्रगति हुई है, लेकिन आजीविका और समुदायों के पुनर्निर्माण पर अभी भी काम किए जाने की आवश्यकता है।' उन्होंने कहा, 'जिन लोगों ने अपने प्रायजनों को खोया और जिनकी जीवन परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं, उनके बारे में सोचकर मुझे लगता है कि उनके घाव अब तक नहीं भरें हैं। समय बीतने के बावजूद वे दर्द आज भी कायम हैं।' जन्मदिन के अवसर पर सम्राट नरुहितो, महारानी मासाको, उनकी पुत्री राजकुमारी अइकी और छोटे भाई काउन प्रिंस अकिशिने के साथ शाही महल की बालकनी में आए और हाथ हिलाकर शुभकामनाएं देने पहुंचे नागरिकों का अभिवादन किया। लोग 'राइजिंग सन' के छोटे-छोटे झंडे चहराकर उनका स्वागत कर रहे थे। वर्ष 2011 की विनाशकारी आपदा में आए भीषण भूकंप और सुनामी से लगभग 20 हजार लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस आपदा के कारण फूकुशिमा दाइवी परमाणु प्लांट में परमाणु रिएक्टर पिघलने (मेल्टडाउन) की घटना भी हुई थी। रेडिएशन के कारण खाली कराए गए अधिकांश इलाकों को दोबारा खोल दिया गया है, लेकिन रोजगार और सामुदायिक ढांचे की कमी के चलते बड़ी संख्या में लोग अब तक वापस नहीं लौटें हैं।

नेपाल में तय समय पर ही होंगे आम चुनाव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले- चुनाव रोकने की खबर गलत

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) रामप्रसाद भंडारी ने कहा कि आगामी चुनाव देश में सुशासन स्थापित करने और संविधान की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं। किसी भी स्थिति में मतदान प्रक्रिया नहीं रुकेगी। काठमांडू में रविवार को भंडारी ने कहा कि चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद तरह-तरह की शंकाएं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं लेकिन इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में चुनाव का कोई विकल्प नहीं होता। कुछ असंतुष्ट तत्व चुनाव टलने की आशंका फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नेपाली जनता ऐसे भ्रम का हिस्सा नहीं बनेगी। भंडारी ने कहा कि पांच मार्च को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। उन्होंने कहा कि सुशासन की अपेक्षा रखने वाले नागरिकों को गुमराह कर अस्थिरता पैदा करने के प्रयास सफल नहीं होंगे। मीडिया से अपील करते हुए भंडारी ने मतदान से पहले मत सर्वेक्षण नहीं करने का आग्रह किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव पूर्व ऐसे सर्वे मतदाताओं की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं और इससे चुनाव की निष्पक्षता पर असर पड़ता है। नेपाल में मधेश प्रांत की गौर नगरपालिका में सांप्रदायिक झड़पों के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालात को देखते हुए फर्फ्यू बरकरार है।

नेपाल-बस हाईवे से नदी में गिरी, 18 की मौत

25 घायल, मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक, कंट्रोल खोने से हादसा

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के धादिंग जिले में सोमवार देर रात एक बस हाईवे से नदी में गिर गई। नेपाली मीडिया के मुताबिक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हैं। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला विदेशी नागरिक शामिल हैं। हालांकि, यह किस देश से थे और इनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं।



आर्मंड पुलिस फोर्स के मुताबिक, अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। बाद में एक अन्य यात्री की मौत की पुष्टि हुई, जिससे मृतकों का आंकड़ा 18 हो गया। हादसे में घायल लोगों को रेस्क्यू कर अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब तक मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी, तभी किसी कारण झड़कर का बस से नियंत्रण खो गया और बस त्रिशूली नदी में जा गिरी। हादसा देर रात करीब रात 1:30 बजे धादिंग जिले के बेनिघाट रोरांग इलाके में हुआ। फिलहाल पुलिस हादसे की अन्य वजहों की भी जांच कर रही है।

हादसे के समय बस में 44 लोग सवार थे

मरने वालों में 12 पुरुषों और 6 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय बस में कुल 44 यात्री सवार थे। घायल 26 यात्रियों को बचा लिया गया है। कुछ का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि अधिकांश को आगे के इलाज के लिए

भारतीयों और एक बस चालक की मौत हुई। भगवान शिव के त्रिशूल से जुड़ी है त्रिशूली नदी

त्रिशूली नदी नका नाम भगवान शिव के त्रिशूल से आया है। इसके पीछे एक प्रचलित कथा है कि गोसाइकुंड (एक पवित्र जगह) में शिव जी ने अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ा, जिससे तीन झरने निकले और ये नदी बनी। ये तिब्बत (चीन) के ग्यिंरो काउंटी में शुरू होती है। वहाँ दो नदियाँ - वियरोंग त्सांगपो और लेंदे खोला से मिलकर त्रिशूली बनाती हैं। नेपाल में ये रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, चितवन जैसे जिलों से गुजरती है।

पृथ्वी हाईवे के साथ-साथ बहती है, जो काठमांडू और पोखरा को जोड़ता है। आखिर में ये नारायणी नदी (गंडकी नदी) में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। पुराने समय में ये काठमांडू वैली और तिब्बत के बीच व्यापार का मुख्य रास्ता था। ये नदी स्थानीय लोगों के लिए पानी, सिंचाई, मछली पकड़ने और संस्कृति का हिस्सा है। पर्यटन (राफ्टिंग, ट्रेकिंग) से भी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। नदी के किनारे कई रिजॉर्ट्स, होटल और गांव हैं, जहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। ये इलाका बौद्ध और हिंदू संस्कृति का मिश्रण है। हालांकि, मानसून में तेज बहाव, लैंडस्लाइड के कारण और यहाँ कई दुखद घटनाएँ हुई हैं।

मैक्सिको में बढ़ती हिंसा के बीच भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, नागरिकों से घर में रहने की सलाह

मैक्सिको, एजेंसी। मैक्सिको में बढ़ती हिंसा और सुरक्षा अभियानों के बीच भारत के दूतावास ने वहाँ रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने भारतीयों से सतर्क रहने, भीड़-भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने और फिलहाल घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी है।



एल मेंचो की मौत से भड़की हिंसा: यह एडवाइजरी उस सैन्य कार्रवाई के बाद जारी की गई है, जिसमें मैक्सिको के सबसे कुख्यात ड्रग कार्टेल सरगना नेमेसियो ओसेगुरा केरवेंटेस उर्फ एल मेंचो को मार गिराया गया। वे जलिसको न्यू जेनेरेशन कार्टेल (एचएनएन) का प्रमुख थे। मेंचो मैक्सिको व अमेरिका के मोस्ट वॉन्टेड अपराधियों में शामिल थे। मैक्सिकन सेना ने पश्चिमी राज्य जलिसको में एक ऑपरेशन के दौरान उन्हें ढेर किया।

अगली सूचना तक सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह: भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलिसको राज्य (प्यूर्टो वल्लार्ता, चापाला और

वाइल्लाहारा), तामाउलिपास राज्य (रेनोसा सहित अन्य नगरपालिकाएँ), मिचोआकान, गुएरेरो और नुएवो लियोन के कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा अभियान, सड़क अवरोध और आपराधिक गतिविधियाँ जारी हैं। ऐसे में भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। दूतावास ने नागरिकों को फोन-व्यवस्था से जुड़े अभियानों के आसपास के इलाकों से दूर रहने, स्थानीय मीडिया पर नजर रखने, अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा है। आपात स्थिति में 911 पर संपर्क करने की सलाह भी दी गई है। साथ ही भारतीयों से अपने परिवार और मित्रों को अपनी स्थिति की जानकारी नियमित रूप से देते रहने की सलाह दी गई है।

ईरान के विश्वविद्यालयों में दूसरे दिन भी सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, अमेरिका से तनाव के बीच बिगड़े हालात

तेहरान, एजेंसी। ईरान के दो बड़े शहरों तेहरान और मशहद में विश्वविद्यालय परिसरों में लगातार दूसरे दिन सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। छात्र समूहों और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार कम से कम सात विश्वविद्यालयों में छात्र झड़प हुए और नारेबाजी की। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के बावजूद छात्रों ने परिसर में प्रदर्शन जारी रखा। यह नया विरोध ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही शनिवार से प्रदर्शन फिर तेज हुए। विचारकों के कई छात्रों ने काले कपड़े पहनकर पहले हुए प्रदर्शनों में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि दी। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट और ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित कई संस्थानों में छात्रों की भीड़ देखी गई।



पहले भी हुआ था बड़ा दमन: जनवरी में हुए देशव्यापी प्रदर्शनों को सुरक्षा बलों ने सख्ती से दबा

समय प्रदर्शनकारियों ने सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के शासन को समाप्त करने की मांग की थी। सरकार की चेतावनी दी: हालिया प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार ने औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सरकारी मीडिया ने परिसरों में तनाव की खबरें दी हैं। तेहरान विश्वविद्यालय के एक अधिकारी हुसैन गोलदानसाज ने छात्रों को 'उग्र नारे' और हिंसा से दूर रहने की चेतावनी दी। सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है।

अमेरिका से बढ़ता तनाव: यह विरोध उस समय हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत जारी है। ओमान की मध्यस्थता में दोनों देशों की वार्ता रिव्ट्रजलैंड में फिर शुरू होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि समाधान संभव है, लेकिन ईरान यूरेनियम संवर्धन का अधिकार नहीं छोड़ेगा। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ाई गई है।

सिनाओला कार्टेल के सरगना एल चापो की गिरफ्तारी और 2024 में अल मायो की गिरफ्तारी के वक्त भी देश में ऐसा ही हुआ था। 2019 में जब अल चापो के बेटे ओविंदियो गुजमान को पकड़ा गया था, तब उसके गुर्गों ने कुलियाकान शहर को घंटों तक बंधक बना लिया था और सरकार को उस खेड़े छोड़ना पड़ा था। इसलिए अब भी डर है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जलिसको कार्टेल के पास नया नेता साफ तौर पर तय है या नहीं। अगर अंदरूनी लड़ाई शुरू हुई तो खून-खराबा और बढ़ सकता है।

मैक्सिको पर एक्शन लेने को दबाव बना रहे थे ट्रम्प: जलिसको कार्टेल कार्टेल विंगडू जाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एल मेंचो की मौत से पहले 2016 में

मेक्सिको में सेना ने सबसे बड़े ड्रग माफिया को मारा

ट्रम्प के दबाव के बाद एक्शन, देशभर में हिंसा शुरू, समर्थकों ने एयरपोर्ट-मॉल में आग लगाई



सिनाओला कार्टेल के सरगना एल चापो की गिरफ्तारी और 2024 में अल मायो की गिरफ्तारी के वक्त भी देश में ऐसा ही हुआ था। 2019 में जब अल चापो के बेटे ओविंदियो गुजमान को पकड़ा गया था, तब उसके गुर्गों ने कुलियाकान शहर को घंटों तक बंधक बना लिया था और सरकार को उस खेड़े छोड़ना पड़ा था। इसलिए अब भी डर है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जलिसको कार्टेल के पास नया नेता साफ तौर पर तय है या नहीं। अगर अंदरूनी लड़ाई शुरू हुई तो खून-खराबा और बढ़ सकता है।

बन गया था। यह कोकीन, मेथामफेटामिन और हाल के वर्षों में फंटाइनल जैसी सिंथेटिक ड्रग्स अमेरिका भेजता था। न्यूयॉर्क था। 2019 में जब अल चापो के बेटे ओविंदियो गुजमान को पकड़ा गया था, तब उसके गुर्गों ने कुलियाकान शहर को घंटों तक बंधक बना लिया था और सरकार को उस खेड़े छोड़ना पड़ा था। इसलिए अब भी डर है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जलिसको कार्टेल के पास नया नेता साफ तौर पर तय है या नहीं। अगर अंदरूनी लड़ाई शुरू हुई तो खून-खराबा और बढ़ सकता है।

मुझे अंधेरे में रखा, मुहम्मद यूनुस पर फायर हुए बांग्लादेश के राष्ट्रपति, हालात बदलते ही बदले जज्बात

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का कार्यकाल खत्म होते ही और आम चुनाव के बाद नई सरकार गठित होने ही राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के जज्बात भी बदल गए हैं। इतने दिनों से मोहम्मद यूनुस की अगुआई में चल रही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर उन्होंने एक भी सवाल नहीं उठाया। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते रहे और भारत के साथ रिश्ते खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अब शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने उन्हें अंधेरे में रखा था।



राष्ट्रपति को अलग-थलग करने में जुटे थे यूनुस

बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने ना तो कभी संस्थानों के बीच समन्वय पर ध्यान दिया और ना ही वह किसी भी फैसले को लेकर उन्हें कोई जानकारी देते थे। राष्ट्रपति ने कहा कि यहां तक कि विदेश दौरे की भी जानकारी उन्हें नहीं होती थी। विदेश नीति से संबंधित कोई भी सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचती ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अलग-थलग करने के लिए सारी राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे थे।

विदेश दौरे पर नहीं लेते थे सलाह

शहाबुद्दीन ने कहा कि सरकार को जरूरी फैसले राष्ट्रपति की सलाह से करने चाहिए लेकिन मोहम्मद यूनुस खुद ही सारे फैसले कर लेते थे। संविधान यह भी कहता है कि विदेश दौरे पर जाते समय राष्ट्रपति को जानकारी देनी चाहिए और लौटने के बाद इसके परिणामों पर चर्चा होनी चाहिए। कार्यकाल के दौरान वह 14 से 15 बार विदेश गए लेकिन एक बार भी उनकी सहमति नहीं ली गई।

राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा, अगर किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता होता है तो इसकी जानकारी राष्ट्रपति को होनी चाहिए लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। ना तो कभी मौखिक और ना ही लिखित रूप में कोई सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। इसके बाद भी वह मुझे नजरअंदाज ही करते थे। वह मुझसे मिलने कभी आए ही नहीं, ऊपर से मुझे अंधेरे में रखते थे।

बेटी नहीं, पार्टी के शीर्ष पद पर चुने गए किम जोंग उन

प्योंगयांग, एजेंसी। तमाम अटकलों के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के शीर्ष पद पर फिर से निर्वाचित किया गया है। बीते कुछ समय से चर्चा चल रही थी कि किम जोंग उन अपनी बेटी को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। किम जोंग उन ने एक बार फिर अमेरिका को आंख दिखाते हुए देश में परमाणु हथियारों को और मजबूत करने का ऐलान किया है। गुरुवार से शुरू हुई पार्टी कांग्रेस में किम अपने पांच वर्षों के लिए अपने प्रमुख राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों की रूपरेखा पेश कर सकते हैं। संकेत मिल रहे हैं कि वह परमाणु कार्यक्रम को और तेज करने पर जोर देंगे। उत्तर कोरिया के पास पहले से ही ऐसी मिसाइल मौजूद हैं जो एशिया में अमेरिकी सहयोगियों और अमेरिकी मुख्य भूमि तक को निशाना बना सकती हैं।



हर पांच वर्ष में होते हैं चुनाव: विश्लेषकों का मानना है कि किम परंपरिक सैन्य बलों को मजबूत करने और उन्हें परमाणु क्षमताओं के साथ एकीकृत करने के नए लक्ष्य घोषित कर सकते हैं। साथ ही वह चीन के साथ व्यापार में सुधार और रूस को हथियार निर्यात से मिली आर्थिक बढ़त के बीच 'आत्मनिर्भरता' अभियान पर भी पुनः

रूस का खुलकर साथ दे रहे हैं। उन ने हजारों सैनिकों को भी रूस की तरफ से युद्ध में उतारा है। वह रूस की यात्रा भी कर चुके हैं। जानकारी का कहना है कि रूस और उत्तर कोरिया मिलकर अपनी सेना को मजबूत करने और परमाणु हथियारों को बनाने पर जोर दे रहे हैं। अटकलें थी कि किम जोंग उन अपनी 16 साल की बेटी को पार्टी का महासचिव बना सकते हैं। बीते दिनों वह किम जोंग उनके साथ नजर आई थीं। हालांकि किम की बेटी किम जू ए अभी नाबालिग हैं। जानकारी के मुताबिक किम जू एक, किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू के तीन बच्चों में तीसरे नंबर पर हैं। वैसे तो किम जोंग उन अपने परिवार को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाते हैं लेकिन उनकी बेटी कई बार उनके साथ दिख चुकी है। फरवरी में उनकी तस्वीरें डाक टिकट पर भी छपी थीं।

रूस से करीबी: किम जोंग उन यूक्रेन युद्ध में

ट्रम्प के रिजॉर्ट में घुस रहे युवक को गोली मारी, मौत गन और फायल केन लेकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था



वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के मार-ए-लागो रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश करने वाले एक युवक को सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना स्थानीय समयानुसार रविवार आधी रात 1:30 बजे हुई। राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाली एजेंसी सीक्रेट सर्विस ने बताया कि युवक गैरकानूनी तरीके से सुरक्षित इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था। वह अपने साथ शॉटगन और फायल केन लेकर आया था। मारे गए युवक की उम्र 20 साल थी, वह नॉर्थ कैरोलीना का रहने वाला था। फिलहाल उसकी पहचान अभी सावजनिक नहीं की गई है। मामले की जांच जारी है। घटना के वक्त राष्ट्रपति ट्रम्प वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में मौजूद थे। आमतौर पर वह वीकेंड पर मार-ए-लागो में समय बिताते हैं।

सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रिजॉर्ट के नॉर्थ गेट से एक कार के बाहर निकल रही थी, इसी दौरान युवक ने अंदर घुसने की कोशिश की। उसके पास शॉटगन और फायल केन थी। सीक्रेट सर्विस के दो एजेंट्स ने उसे रोका और उससे हथियार और केन गिराने को कहा

गया। युवक ने केन तो रख दिया, लेकिन शॉटगन को गोली चलाने की पोजिशन में उठा लिया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई और वह मारा गया। जांच में पता चला कि उसके परिवार ने कुछदिन पहले उसे लापता होने की रिपोर्ट की थी। वह नॉर्थ कैरोलीना से साउथ की ओर आया था और रास्ते में शॉटगन खरीदा। उसकी कार में गन का डिब्बा मिला है। ट्रम्प की सुरक्षा में पहले भी चूक हो चुकी है। 13 जुलाई 2024 में ट्रम्प को एक रैली के दौरान एक हमलावर ने गोली मार दी थी। उस वक्त वे राष्ट्रपति नहीं थे। उन पर यह हमला राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 4 महीने पहले हुआ था।

20 साल के हमलावर ने 400 फीट की दूरी से ट्रम्प पर असॉल्ट राफेल से गोली चलाई थी। यह गोली उनके कान को छूते हुए गुजरी थी। इसके बाद ट्रम्प की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्टाफर्स ने हमलावर को तुरंत ढेर कर दिया था। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के पास होता है। यह एक फेडरल एजेंसी है, जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तहत काम करती है। सीक्रेट सर्विस की शुरुआत 1865 में हुई थी।

एक्स मुवनेश्वर में लिबर प्रत्यारोपण यूजिट और रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत

एजेंसी
नई दिल्ली। भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में लिबर प्रत्यारोपण यूजिट और रोबोटिक सर्जरी सिस्टम की शुरुआत हुई। इस नई सुविधा में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक इंटेसिव केयर यूजिट और लिबर ट्रांसप्लंट स्पेशलिटी क्लिनिक शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इन सुविधाओं का वचुंअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद अपराजिता सारंगी और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य शलिला श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि एम्स भुवनेश्वर के लिए आज गां व का स है, जो तुतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा अनुसंधान में उत्कृष्टता हासिल कर रहा है। यह कदम ओडिशा और पूर्वी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने और मरीजों को उच्च तकनीक और जीवनरक्षक इलाज सुलभ करने की दिशा में मील का पथर साबित होगा। उन्होंने कहा कि नई लिबर ट्रांसप्लंट सुविधा से ओडिशा और पूर्वी भारत के मरीजों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम और पड़ोसी राज्यों के लोगों को उच्च स्तरीय जीवनरक्षक इलाज अब घर के नजदीक ही उपलब्ध होगा। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए यह सुविधा मुफ्त या कम लागत पर उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने की मुलाकात

रांची। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से आल झारखंड स्टूडेंट्स युनियन (आजसू) पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सुदेश महतो की यह पहली भेंट थी। इस अवसर पर सुदेश महतो ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत होगा। मुलाकात के दौरान झारखंड में राजग को सशक्त करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही आसम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। मुलाकात के बाद सुदेश महतो ने अपने 'एक्स' (पूर्व दिवटर) हैंडल पर लिखा कि राजग का संकल्प राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नितिन नवीन के नेतृत्व में राजग की एकता और अधिक सुदृढ़ होगी तथा जनसेवा और विकास की राजनीति को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी।

दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने दिल्ली विधान सभा को बम से उड़ाने की धमकी की निंदा करते हुए देशियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के पर्सनल ई-मेल पर बम ब्लास्ट की धमकी प्राप्त हुई है, जिसमें दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को प्राप्त ईमेल की जानकारी देते हुए तुरंत आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के सचिव विनोत कुमार ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर धमकी वाले ईमेल की जानकारी साझा करते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। धमकी वाले ईमेल में खालिस्तान नेनाल आर्मी का जिक्र किया गया है। यह धमकी वाला ईमेल सोमवार सुबह 08.57 बजे दिल्ली विधानसभा की पर्सनल ईमेल पर kristalburnette-x@gmail.com से और सुबह 09.08 बजे फिर webb-bryonl@gmail.com से भेजा गया है। पत्र में दोनों ईमेल आईडी की जानकारी देते हुए बम धमकियों के बारे में गंभीर चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए इन ईमेल के सोर्स का पता लगाने के लिए जांच करने को कहा गया है। धमकी मिलने के तुरंत बाद दिल्ली विधानसभा परिसर के साथ-साथ अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के आवास पर बम निरोधक दस्ते ने तलाशी अभियान चलाया।

आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में मिलावटी दूध से पांच लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान

राजमुंदरी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राजमुंदरी के चौदहवरी नगर और स्वरूप नगर में स्थानीय लोगों के बीमार पड़ने की घटना पर विधानसभा में बयान दिया। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुःख बताया है और कहा कि लाला चेरुवु इलाके में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आठ लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में बलरामि डेयरी के मिलावटी दूध के सेवन से लोगों के बीमार पड़ने की पुष्टि हुई है। इस मामले में जिम्दार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्वी गोदावरी की जिलाधिकारी कीर्ति चेकुरी ने बताया कि कुल 106 परिवारों को दूध की आपूर्ति की गई थी। इनमें से 12 लोगों में किडनी से जुड़ी समस्या पाई गई और पांच लोगों की मौत हो गई। 73 लोगों के रक्त नमूने लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट जल्द ही आने की संभावना है। जिलाधिकारी ने बताया कि दूध के नमूने जांच के लिए हैदराबाद भेजे गए हैं।

जम्मू के अखनूर में विदेशी नोटों से बंधे पाकिस्तानी गुब्बारे बरामद

जम्मू। जम्मू के पास अखनूर सेक्टर के एक अग्रिम गांव से दो गुब्बारे बरामद किए गए। एक गुब्बारे पर एक पाकिस्तानी 5,000 रुपये का नोट और एक अमेरिकी डॉलर बंधा हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि हवाई जहाज के आकार के सफेद और लाल गुब्बारे खुर सीमा क्षेत्र के गुनार गांव में एक पेड़ पर चिपके हुए मिले। इन गुब्बारों पर एक पाकिस्तानी मोबाइल नंबर और एक क्यूआर कोड भी अंकित था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पाकिस्तान की ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा के इस तरफ हवा के साथ बहकर आए थे। सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान से आने वाले गुब्बारों का आना एक आम बात है, लेकिन यह पहली बार है कि इन पर विदेशी नोट बंधे हुए पाए गए हैं। बीएसएफ ने रविवार को भी पाकिस्तान की ओर से सीमा पार करके सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के खेतों में फिर 16 लाल गुब्बारे जल किए थे।

जम्मू के पास अखनूर सेक्टर के एक अग्रिम गांव से दो गुब्बारे बरामद किए गए। एक गुब्बारे पर एक पाकिस्तानी 5,000 रुपये का नोट और एक अमेरिकी डॉलर बंधा हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि हवाई जहाज के आकार के सफेद और लाल गुब्बारे खुर सीमा क्षेत्र के गुनार गांव में एक पेड़ पर चिपके हुए मिले। इन गुब्बारों पर एक पाकिस्तानी मोबाइल नंबर और एक क्यूआर कोड भी अंकित था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पाकिस्तान की ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा के इस तरफ हवा के साथ बहकर आए थे। सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान से आने वाले गुब्बारों का आना एक आम बात है, लेकिन यह पहली बार है कि इन पर विदेशी नोट बंधे हुए पाए गए हैं। बीएसएफ ने रविवार को भी पाकिस्तान की ओर से सीमा पार करके सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के खेतों में फिर 16 लाल गुब्बारे जल किए थे।

राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गुणवत्ता जांच के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन शुरू की

एजेंसी
नई दिल्ली। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन (एमक्यूसीवी) की शुरुआत की है। इस पायलट परियोजना को राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य निर्माण कार्य की गुणवत्ता की मांके पर ही जांच करना है। मंत्रालय ने बताया कि मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन चलती-फिरती प्रयोगशाला की तरह काम करती है। इसमें ऐसे आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिनसे बिना निर्माण कार्य को नुकसान पहुंचाए गुणवत्ता की जांच की जा सकती है। इससे निर्माण की मजबूती, टिकाऊपन और सुरक्षा का आकलन किया जा सकेगा। इन वैन में रिबाउंड हैमर लगाया गया है। यह उपकरण कंक्रीट की सतह की उपकरण लगाए गए हैं, जिनसे बिना निर्माण कार्य को नुकसान पहुंचाए गुणवत्ता की जांच की जा सकती है। इससे निर्माण की मजबूती, टिकाऊपन और सुरक्षा का आकलन किया जा सकेगा। इन वैन में रिबाउंड हैमर लगाया गया है। यह उपकरण कंक्रीट की सतह की

मेडिकल ट्रेवल इकोसिस्टम होगा मजबूत, अंतर-मंत्रालयी और नियामक समन्वय पर रहेगा जोर: जेपी नड्डा

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि मेडिकल ट्रेवल केवल आर्थिक अवसर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विश्वास निर्माण का माध्यम भी है। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार अंतर-मंत्रालयी और नियामक समन्वय बढ़ा रही है। 'एडवांटेज हेल्थ केयर- इंडिया 2026' के 8वें संस्करण को वचुंअल रूप से संबोधित करते हुए कहा जेपी नड्डा ने कहा कि यह आयोजन सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा गतिशीलता के भविष्य को सामूहिक रूप से आकार देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।



की जाने वाली विशाल क्षमता का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री (फिककी) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत, स्तर के मानकों और मरीज-केंद्रित देखभाल का प्रतीक है। भारत के कुशल डॉक्टर, आधुनिक अस्पताल और डिजिटल हेल्थ तकनीकों काडिओलॉजी, कैसर उपचार, अंग प्रत्यारोपण, ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोसाइंसेज जैसे क्षेत्रों में

गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण की दिशा में व्यापक सुधार कर रहा है। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल भारत की क्लिनिकल उत्कृष्टता, अंतरराष्ट्रीय

शंकराचार्य से मिले अजय राय, बोले— 'संतों के सम्मान पर आंच बर्दाशत नहीं'

एजेंसी
वाराणसी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केदारनाथ स्थित विद्या मठ पहुंचकर ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत समाज के सम्मान पर किसी भी प्रकार की आंच बर्दाशत नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य को सुनियोजित साजिश के तहत बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अजय राय ने कहा कि मोदी-योगी सरकार शंकराचार्य के खिलाफ साजिश रच रही है। उनके अनुसार, 'भगवान शंकराचार्य जी का अपमान पूरे सनातन धर्म का अपमान है। शंकराचार्य भगवान के स्वरूप हैं। हम काशीवासी और कांग्रेसजन उनके साथ मजबूती से खड़े हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की तानाशाही ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और जनता समथ



संतों और धर्माचार्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाना भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर तथ्य और प्रमाण के साथ जनता के बीच सच्चाई रखेगी और संत समाज की गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस

पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक पूरी ताकत के साथ उठाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संत समाज के सम्मान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुलाकात के दौरान जिला अध्यक्ष

राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, अनिल श्रीवास्तव, प्रजानाथ शर्मा, संतनाथ सिंह, मनीष मोरोलिया, अल्पप्रकाश ओझा, अरुण सोनी, राजीव गौतम, राजू राम, प्रमोद वर्मा, संतोष चौरसिया, सदानंद तिवारी, आशीष तिवारी समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

वीबी जी रामजी अधिनियम रोजगार का अधिकार छीन रहा : सिद्धारमैया

एजेंसी
बिष्णुगढ़। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वीबी जी रामजी अधिनियम ग्रामीण गरीबों के रोजगार के अधिकार को छीन रहा है और इसे निरस्त कर मनरेगा को बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य की जनता से कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का समर्थन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने आज चिक्काबल्लापुर में आयोजित 'नरेगा बचाओ' आंदोलन में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देशभर में 'मनरेगा बचाओ' अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने शीकालीन सत्र के दौरान मनरेगा को निरस्त कर नया कानून लागू किया है। सिद्धारमैया ने कहा कि महत्वा



ओं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में

उन्होंने कहा कि महत्वा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार को साकार करने में मनरेगा सहायक था। इसके तहत ग्राम

पंचायतों का स्वशासन प्रभावित होगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि नए प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकारें 40 प्रतिशत अनुदान देंगी, जिससे राज्यों के अधिकार और हित प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि वीबी जी रामजी योजना को पूरी तरह समाप्त कर मनरेगा को पुनः लागू किया जाए, पंचायतों के अधिकार बहाल किए जाएं तथा देशभर में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन तय की जाए। सिद्धारमैया ने कहा कि किसान विरोधी कानूनों की तरह यह संघर्ष भी तब तक जारी रहेगा, जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं। उन्होंने राज्य के नागरिकों के तहत निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार के पास केंद्रित किया जा रहा है, जिससे

छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा 26 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर

एजेंसी
रायपुर। छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्याय (डीएमएफ) घोटाला मामले में आज आरोपित पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपित को रायपुर में विशेष एसीबी/ईओडब्ल्यू अदालत में पेश किया गया। जहां से 26 फरवरी 2026 तक की पुलिस रिमांड की अनुमति दी गई है। यह कार्रवाई ब्यूरो के दूर अर्पण की विस्तृत जांच के बाद की गई है।

जॉर्ज के दौरान मिले डिजिटल सबूत, दस्तावेज और गवाहों के कारोबारी अनवर डेबेर को भी गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि 2019-20 से 2023-24 के बीच ओवरटाइम के नाम पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ। यह पैसा शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलना था, लेकिन कर्मचारियों तक पूरी रकम नहीं पहुंची। ब्यूरो के



के दायरे में है। इसके अलावा शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने कारोबारी अनवर डेबेर को भी गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि 2019-20 से 2023-24 के बीच ओवरटाइम के नाम पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ। यह पैसा शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलना था, लेकिन कर्मचारियों तक पूरी रकम नहीं पहुंची। ब्यूरो के

ओम बिरला ने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह गठित किए

एजेंसी
नई दिल्ली। भारत के संसदीय कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूहों के गठन की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों की संसदों के साथ प्रत्यक्ष, नियमित और संस्थागत संवाद को बढ़ावा देना है, ताकि पारंपरिक राजनय के साथ-साथ संसदीय स्तर पर भी द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ किया जा सके। इन मैत्री समूहों में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के संसदों को शामिल किया गया है, जो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। बरिष्ठ नेताओं में रवि शंकर प्रसाद, डॉ. एम. थंबीदुरई, पी. चिदंबरम, प्रो. राम गोपाल यादव, टीआर बालू, डॉ. काकोली घोष दत्तौदार, गौरव गोरोई, कनिमोड़ी करुणानिधि, मनीष तिवारी, डेरेक



ओ'ब्रायन, अभिषेक बनर्जी, असेदुल्ला ओवैसी, अखिलेश यादव, केंसी वेणुगोपाल, राजीव प्रताप रूडी, सुप्रिया सुले, संजय सिंह, बैजवंत पांडा, शशि थरूर, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, भर्तृहरि महापात्र, डी. पुरंदेश्वरी, संजय कुमार झा, हेमा मालिनी, बिष्णु कुमार देव, डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, जगदीशका पारंग, डॉ. संसिमता पात्रा, अपराजिता सारंगी, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, पीवी मिथुन रेड्डी और प्रफुल्ल पटेल को विभिन्न देशों से संबंधित समूहों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन देशों के साथ मैत्री

गुरुदासपुर में पुलिस अधिकारियों की हत्या की एनआईए से हो जांच:भाजपा

एजेंसी
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब के गुरुदासपुर जिले की सीमा चौकी पर पुलिस के दो जवानों की हत्या पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बहादुर अधिकारियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और पूरा देश उनके शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। चुग ने यहां पत्रकारों से बातचीत में इस घटना को बेहद चिंताजनक और एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला बताया। उन्होंने पुलिस चौकी की भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से निकटता और सीमा पार से संभावित सल्लसला के उभरते संकेतों को देखते हुए इस पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से करवाने की मांग की।

उन्होंने कहा कि यह मामला इतना गंभीर है कि इसे राज्य स्तरीय जांच के बरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। चुग ने भगवत मान के नेतृत्व वाली सरकार को पंजाब में विघटनकारी और राष्ट्रविरोधी ताकतों को पनपने देने के लिए सीधे तौर पर दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि यह हत्या अमृतसर में एक पुलिस स्टेशन को उड़ाने की हालिया धमकियों के ठीक बाद हुई है और मोहाली स्थित पुलिस मुख्यालय सहित राज्यभर में पुलिस प्रस्थानों पर हुए एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों के बाद हुई है। उच्च सुरक्षा वाली जेलों के अंदर से संचालित होने वाले आपराधिक गिरोहों से लेकर ड्रोन के जरिए सीमा पार हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी तक, पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति खतरनाक होती जा रही है।

अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामला: ईडी ने 2,300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का किया खुलासा

एजेंसी
बंगलुरु। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों से जुड़े एक बड़े मामले में पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। यह शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दायर की गई है। इस मामले में केंसी वीरेंद्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि पृथ्वी एन राज, केंसी थिपेस्वामी, फोर्पेसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गुलशन खट्टर, पपीज टूंस एंड ट्रेवल्स एलएलपी, अर्जुन नागभूषण, अभिजीत सज्जन और लॉजिकफोर्ज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य लोगों और संस्थाओं के नाम भी शामिल हैं। ईडी ने यह जांच भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कई राज्यों में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इन एफआईआर में किंग567, प्ले567, प्लेविन567, गेमेक्स और अन्य संबंधित



अवैध रूप से कमाई गई रकम को अलग-अलग पेमेंट गेटवे, फर्जी या म्यूल अकाउंट्स, विदेशी संस्थाओं, वचुंअल डिजिटल एसेट्स और विदेशों में भेजी गई रकम के माध्यम से घुमाया गया। इससे पहले ईडी ने कर्नाटक और अन्य राज्यों में 60 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, सोने

की ईंटें, सोने-चांदी के आभूषण, वाहन, डिजिटल उपकरण और कई आपतिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे। ईडी ने केंसी वीरेंद्र को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। साथ ही 29 जनवरी 2026 को करीब 177.30 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की गई थीं। अब तक इस मामले में 320 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच या जब्त की जा चुकी है। ईडी के अनुसार, अब तक 2,300 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध से अर्जित धनराशि की पहचान की गई है, जिसे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के जरिए कमाया गया और बाद में विभिन्न तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तर्ज में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने दुबई समेत विदेशों में संपत्तियां खरीदीं और क्रिप्टो एसेट्स में भी लेनेदान किए। ईडी ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की मांग: कांग्रेस देश से माफी मांगे

एजेंसी
बंगलुरु। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एआई शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के कथित व्यवहार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे 'बेहद चौंकाने वाला और खेदजनक' बताया हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को देश से माफी मांगनी चाहिए।

बंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस के इस रुख को आलोचना उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी की है। उन्होंने बरिष्ठ नेता मारिटे अल्वा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सम्मेलन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर 'अनुशासन, गरिमा और विवेक'

बनाए रखना चाहिए था। जोशी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान का भी उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने भी अलग अंदाज में इसी भावना को व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, एआई शिखर सम्मेलन में 29 देशों के प्रतिनिधि, 45 मंत्री, देश के प्रमुख उद्योगपति तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित थे।

ऐसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर कांग्रेस का आचरण अनुचित रहा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद राहुल गांधी से देश की जनता से माफी मांगने की मांग दोहराई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं को भविष्य में शालीनता और मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी।

बिरला ने कहा कि संसदीय कूटनीतिक भारत की वैश्विक पहचान को सशक्त बनाती है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की भूमिका को और प्रभावी बनाती है।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संसद से संसद और जनता से जनता के बीच संपर्क बढ़ाना समय की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजकर राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भारत की एकजुटता साहित देखा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा अध्यक्ष की यह पहल वैश्विक मंच पर भारत की सशक्त, समावेशी और संवाद-आधारित लोकतांत्रिक छवि को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पहले करण में 60 से अधिक देशों के साथ मैत्री समूह गठित किए गए हैं और निकट भविष्य में अन्य देशों के साथ भी ऐसे समूह स्थापित किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

अन्य खामियों का पता लगाता है। इससे छिपी हुई कमजोरियों की पहचान संभव होती है। वैन में एस्फाल्ट घनत्व मापक भी लगाया गया है। यह उपकरण सड़क की परत की सघनता की जांच करता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रहे। इसी तरह हल्का विक्षेप मापक भी इसमें शामिल है। यह मिट्टी और आधार परत की मजबूती का आकलन करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सड़क का आधार मजबूत है। मंत्रालय ने बताया कि वैन में रिफ्लेक्टोमीटर भी लगाया गया है।

पार्इ जाती है तो संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग गुणवत्ता निगरानी पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल पर जांच रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध होगी।



इंडो-हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी प्रियामणि

प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से निकलकर हॉलीवुड में एक अलग मुकाम बनाया है। साथ ही बाकी भारतीय कलाकारों के लिए भी राह खोली है। प्रियंका की राह पर चलते हुए साउथ एक्ट्रेस प्रियामणि भी अब एक इंडो-हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रही हैं। इसमें उनके साथ टीवी पर 'महादेव' का किरदार निभाने वाला एक चर्चित एक्टर नजर आएगा।

मोहित रैना होंगे प्रियामणि के अपोजिट

इस फिल्म में प्रियामणि के अपोजिट टीवी के चर्चित एक्टर मोहित रैना नजर आएंगे। वह बॉलीवुड फिल्मों और सीरीज में भी दमदार किरदार निभा चुके हैं। लेकिन टीवी सीरियल 'देवों के देव महादेव' में उन्होंने भगवान शिव की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का हिस्सा बनने पर मोहित रैना कहते हैं, 'यह प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि यह पहचान और अपनेपन को बहुत इमानदारी से दिखाता है।' वहीं प्रियामणि ने कहा, 'जिस चीज ने मुझे तुरंत इस फिल्म की तरफ खींचा, वह थी कहानी का इमोशन और सच्चाई।' यूएस बेस्ड रेड बाइसन प्रोडक्शंस ने इस क्रॉस बॉर्डर फीचर फिल्म के लिए मुंबई के एज्योर एंटरटेनमेंट के साथ पार्टनरशिप की है। यह फिल्म हर्ष महादेश्वर द्वारा लिखी गई। वहीं इसका डायरेक्ट करेंगे। अभी तक फिल्म का टाइटल नहीं रखा गया है। यह एक फीचर फिल्म होगी, जिसकी कहानी सच्ची कहानी पर आधारित है। इसमें एक अप्रवासी परिवार की भावुक कहानी दिखाई जाएगी। यह प्रोजेक्ट अप्रैल 2026 में शुरू होगा।



युवराज सिंह की बायोपिक करना चाहते हैं सिद्धांत चतुर्वेदी

अपनी आगामी फिल्म 'दो दीवाने सहर में' को लेकर चर्चा में बने अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक बार फिर अपने उस ड्रीम रोल के बारे में खुलकर बात की है, जो सालों से उनके दिल के बेहद करीब है। जी हाँ, अपने करियर की शुरुआत क्रिकेट पर आधारित वेब सीरीज 'इनसाइड एज' से करनेवाले सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक बार फिर क्रिकेट की तरफ लौटते हुए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह की बायोपिक करने की इच्छा जताई है। गौरतलब है कि अमेज़ॉन प्राइम विडिओ के वेब सीरीज 'इनसाइड एज' में क्रिकेट की चमक-दमक के पीछे की अंधेरी दुनिया को सिद्धांत ने बखूबी उकेरा था। फिलहाल बायोपिक के संदर्भ में सिद्धांत कहते हैं, 'मैं वर्ष 2019 से कहता आ रहा हूँ और आज भी कहूँगा और कहूँगा, बल्कि इसे मैनिफेस्ट भी करता हूँ एक दिन मुझे मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह की बायोपिक करने का मौका मिले। उनकी जर्नी एक रोलरकोस्टर की तरह वाकई अविश्वसनीय रही है। मुझे वे न सिर्फ क्रिकेटर के तौर पर पसंद हैं, बल्कि व्यक्तित्व भी उनका

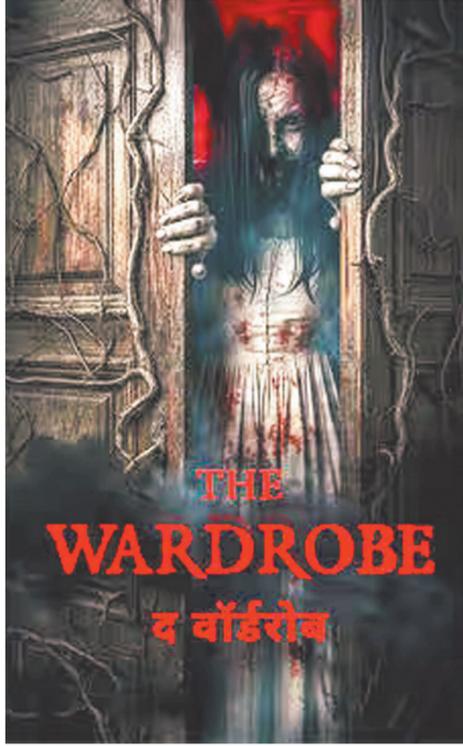
शानदार है। मैं उनके क्रिकेट के साथ उनकी लाइफस्टाइल, और समस्याओं के प्रति उनके जल्बे को सलाम करता हूँ, जिस तरह उन्होंने परेशानियों को मात दी। वाकई वे एक आइकन हैं, और दुनिया को उनकी कहानी जरूर जाननी चाहिए।' वैसे बायोपिक की बात करें तो सिद्धांत जल्द ही दिग्गज फिल्ममेकर 'वी. शांताराम' का चुनौतीपूर्ण बायोपिक में नजर आनेवाले हैं और इसके फर्सट लुक के साथ ही वे अपने दर्शकों की सराहना भी पा चुके हैं।



अब 'प्रोड्यूसर' बन लोगों का दिल जीतेंगी नित्या मेनन

अपने अभिनय से लोगों के दिलों में राज करने वाली साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री नित्या मेनन अब नई शुरुआत करने जा रही हैं। अभिनेत्री ने बताया कि वे अब बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू करने जा रही हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने नए प्रोडक्शन हाउस का ऐलान किया। अभिनेत्री नित्या मेनन ने लिखा, 'मेरे लिए फिल्मों बनाना सिर्फ कहानियाँ सुनाना नहीं है, बल्कि दिल से दिल जुड़ने का तरीका है। जब मैं कुछ बनाती हूँ तो यह न सिर्फ दर्शकों को बदलता है, बल्कि मुझे भी बदल देता है।' अभिनेत्री ने बताया कि रचनात्मक प्रक्रिया में डूबकर मैं खुद में बदलाव महसूस करती हूँ और जो इसे देखते हैं, उनके अंदर भी एक हल्का-सा परिवर्तन आता है। अभिनेत्री ने लिखा, 'यह बदलाव शुरू में शायद नजर न आए,

लेकिन यह हमेशा के लिए असर छोड़ जाता है। फिल्म बनाना मेरे लिए व्यक्तित्व के उस सच्चे और संवेदनशील हिस्से को छूने जैसा है, जो सबसे असली होता है, जब मैं अभिनय करती थी। उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं प्रोड्यूसर बनूँगी और अब प्रोड्यूस करने पर भी यही सोच बनी रहेगी। आपके सामने पेश है- कीयूरी प्रोडक्शंस।' वीडियो में बताया गया है कि केयूरी धरती की गुफाओं से निकली है, चट्टान से बनी है, रोशनी से प्यार करती है, और किसी खास रूप में नहीं बंधी है। यह नाम और उसका मतलब नित्या की रचनात्मक सोच को दर्शाता है, जहां वे ऐसी कहानियाँ बनाना चाहती हैं जो गहरी भावनाओं को छूएँ और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएँ। नित्या मेनन साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। वे अभिनेत्री होने के साथ-साथ पार्श्व गायिका भी हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 'थिरुचित्राम्बल' (2022) के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और चार फिल्मफेयर अवार्ड साउथ मिल चुके हैं। साल 1998 में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाली नित्या मेनन बॉलीवुड की फिल्म 'मिशन मंगल' में नजर आई थीं।



'द वॉर्डरोब' से होगा दिव्या अग्रवाल का बॉलीवुड डेब्यू

अपकमिंग बॉलीवुड हॉरर फिल्म 'द वॉर्डरोब' का फर्सट-लुक पोस्टर आ गया है। टीवी रियलिटी शोज की विजेता रह चुकी दिव्या अग्रवाल इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं।



पोस्टर में एक पुरानी, आधी खुली लकड़ी की अलमारी से एक रहस्यमयी महिला बाहर आती दिखाई दे रही है। अलमारी के अंदर से निकलती लाल रोशनी उसके खून से सने सफेद गाउन को और आघात बना रही है। चारों ओर धुआँ, गहरे साप और खोफ का माहौल, पूरा सीन किसी डरावने सपने जैसा लगता है। लाल रंग में लिखा फिल्म का टाइटल 'द वॉर्डरोब' अंधेरे बैकग्राउंड पर और भी डरावना एहसास दे रहा है। दिव्या ने कहा, 'इस फिल्म ने मुझे एक कलाकार के तौर पर चैलेंज किया। कहानी बहुत प्रिपिंग और एटमॉस्फेरिक है। मैं चाहती हूँ कि दर्शक इसे जल्द से जल्द देखें।' वहीं रजनीश दुग्गल ने भी फिल्म की स्क्रिप्ट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें सरस्येस और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का शानदार बेलेंस है। फिल्म की कहानी एक साधारण-सी दिखने वाली अलमारी से शुरू होती है, जो धीरे-धीरे डरावनी घटनाओं की एक लंबी कड़ी को जन्म देती है। टिक्स्ट, शॉक और रहस्य से भरी यह कहानी दर्शकों को सीट से बांधे रखने पर मजबूर कर सकती है। फिल्म 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' की टक्कर से बचकर निकले सनी देओल; आगे खिसकी 'गबरू' की रिलीज डेट

सनी देओल अभिनीत फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबर्दस्त तरीके से सफल हुई है। इस बीच वे अपने आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं, जिनमें फिल्म 'गबरू' का भी नाम है। पहले यह फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली थी। मगर, अब दर्शकों को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रिलीज डेट में बदलाव किया गया है।

'गबरू' कब होगी रिलीज? 'बॉर्डर 2' के बाद सनी देओल के फैंस की नजर उनकी आगामी फिल्मों पर टिकी है। शशांक उदयपुरकर निर्देशित यह फिल्म पहले 13 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। मगर, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक, यह फिल्म 08 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हाल ही में इन्हें के साथ बातचीत में सनी देओल ने 'गबरू' को अपने दिल के सबसे करीब फिल्मों में से एक बताया। फिल्म 'चांद मेरा दिल' से होगा टकराव फिल्म 'गबरू' को विशाल राणा और ओम छगानी के प्रोड्यूस किया है। फिल्म में सनी देओल के साथ सिमरन और प्रीत कमानो अहम रोल में हैं। सनी देओल की 'गबरू' की रिलीज डेट में बदलाव के बाद अब इसका मुकाबला लक्ष्य ललवानी और अनन्ना पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' से होगा। यह फिल्म भी 08 मई को रिलीज होने वाली है। अनन्ना और लक्ष्य की फिल्म को करण जोहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है।

'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' से बच निकले सनी देओल

बता दें कि मार्च में दो बड़ी फिल्मों सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं। रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और यश की 'टॉक्सिक'। दोनों ही फिल्मों 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही हैं। 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जबर्दस्त तरीके से सफल रही। इसके दूसरे पार्ट का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ, 'टॉक्सिक' का भी क्रैज है। संभवतः इन दोनों फिल्मों से भिड़त से बचने के लिए मेकर्स ने सनी देओल की 'गबरू' की रिलीज में बदलाव किया है।



फिल्म बनाने के लिए प्रियंका ने किया प्रेरित



मीरा चोपड़ा साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के अलावा प्रियंका चोपड़ा की कजिन बहन के तौर पर पहचानी जाती हैं। शादी के बाद वह फिल्मों से दूर थीं लेकिन अब बतौर फिल्ममेकर उन्होंने साइलेंट फिल्म 'गांधी टॉक्स' के साथ वापसी की। हमसे खास बातचीत में उन्होंने अपने करियर, प्रियंका चोपड़ा की सलाह सहित कई विषयों पर बात की। बतौर फिल्ममेकर डेब्यू करने के बाद क्या वह आगे अपनी फिल्म में बहन प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करने के बारे में सोचती हैं। इस सवाल के जवाब में

उन्होंने हंसते हुए कहा, 'नहीं...नहीं। अभी तो मैं वो नहीं कर सकती। मैं अभी उनको एफोर्ड ही नहीं कर सकती हूँ। मैं कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचती हूँ। हाँ जब बड़ी फिल्ममेकर बन जाऊँगी तो एक दिन अपनी फिल्म में प्रियंका को कास्ट करना चाहूँगी।' बिजनेस में हाथ आजमाने के मीरा के फैंसले पर बहन प्रियंका चोपड़ा का क्या रिएक्शन था? इस बारे में वह बताती हैं, 'मैंने सीधे उन्हें अपनी फिल्म 'गांधी टॉक्स' का टीजर भेजा। मैंने उनको बताया कि ये फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है। उनको इस पर बहुत गर्व महसूस हुआ। प्रियंका का व्यवहार कुछ ऐसा है कि हम में से कोई जब कुछ अच्छा करता है, तो वह बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। प्रियंका ने मुझे कहा था कि फिल्म बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, आपने टीजर बना दिया है तो प्लीज अब फिल्म बनाओ। दरअसल, उन्होंने इस इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि इस वर्ल्ड में जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है, वो ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं। जब आपके परिवार में ऐसा कोई होता है तो आप उससे प्रेरित होते हैं। आप पहले उसको देखते हैं। हमेशा एक चाह थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि प्रियंका कहे कि मुझे तुम पर गर्व है और उन्होंने ऐसा कहा, ये मेरे लिए ये बड़ी है।

एक्टिंग में लगातार काम नहीं मिलता एक इंटरव्यू में मीरा ने कहा था कि वह स्क्रीन पर वापसी के लिए लोगों के संपर्क में हैं। लेकिन अब वह बतौर फिल्ममेकर वापसी कर रही हैं। क्या शादी के बाद एक्टिंग में लौटना उनके लिए चुनौती भरा फैसला है? इस पर वह कहती हैं, 'मेरे सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं आई। लेकिन एक्टिंग में क्या है कि आपको दो साल काम नहीं मिला तो आप काम नहीं करोगे, फिर एकदम से एक ही साल में दो प्रोजेक्ट आ जाएँ तो आप काम करोगे। दरअसल, एक्टिंग ऐसा पेशा नहीं है कि

लगातार आपको काम दे ही देगा। मैं ऐसा प्रोफेशनल चाहती थी कि आपका लगातार काम चलता रहे, इसलिए मैंने प्रोडक्शन का काम शुरू किया। वो मेरे कंट्रोल में है कि मुझे कब क्या बनाना है, क्या करना है। एक्टिंग में तो जब प्रोजेक्ट मिलेगा, जब आपको कुछ अच्छा लगेगा तब आप कर पाओगे। मैंने तीन साल काम करने के बाद फिर सोचा कि अब एक्टिंग में वापसी करूँगी और बहुत जल्द मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगी। एक्टिंग मेरा प्यार है, मैं जिंदगी में चाहे कुछ भी करूँ, एक्टिंग नहीं छोड़ूँगी।'

फिल्म के गाने बनाने में समय लग गया

साइलेंट फिल्म के साथ बतौर प्रोड्यूसर वापसी करना और फिल्म की स्क्रीनिंग के लंबे समय बाद रिलीज करना कितनी बड़ी चुनौती थी? इस बारे में वह कहती हैं, 'जब हमने स्क्रीनिंग की थी तो हमारा मकसद था कि इतना बड़ा स्टेप उठाने पर लोगों का रिएक्शन कैसा रहेगा, जो कि काफी अच्छा था। फिर हमने एक बड़ा बदलाव किया कि फिल्म का संगीत पांच भाषाओं में बनाएँगे, क्योंकि फिल्म में डायलॉग नहीं थे तो फिल्म को एक भाषा में रिलीज करना हमें सही नहीं लगा। इसलिए ए.आर रहमान सर ने शुरू से फिल्म का संगीत बनाना शुरू किया। हिंदी के गाने पहले से ही तैयार थे, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मराठी के गाने बनाने शुरू किए। उसमें एक साल और लग गया। लेकिन हमारी मंशा थी कि चाहे एक-दो साल लग जाएँ लेकिन जब फिल्म दर्शकों के सामने आए तो लोगों की वाहवाही मिले।



जब मौसम करे उदास!

हमारी दिनचर्या ऋतु आधारित होती है। हम मौसम के अनुसार ही हम अपना खानपान, पहनावा और रोजमर्रा के काम तय करते हैं। लेकिन मौसम अपने साथ एक खास तरह की बीमारी भी लाता है, क्या यह आप जानती हैं? मौसम के साथ आने वाली इस विशेष बीमारी को सैड यानी सीज़नल इम्फेक्टिव डिस्ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, जो अवसाद का ही एक रूप है। यह किसी व्यक्ति को खास मौसम में हर बार अवसादग्रस्त बना देता है।

कारण अनजान है

सीज़नल इम्फेक्टिव डिस्ऑर्डर क्यों होता है और इसके होने की वजह क्या है, इसे लेकर सेहत के जानकार आज भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उनका मानना है कि सूरज की रोशनी की कमी इस डिस्ऑर्डर को बढ़ाती है। यह कमी व्यक्ति के उठने-बैठने और सोने के क्रम को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से मस्तिष्क में मौजूद रसायन सेरोटिन पर असर पड़ता है, जो मूड बदलने का कारण है।

लक्षण आसान है

इस डिस्ऑर्डर का सीधा संबंध क्योंकि मूड से है, इसलिए इसके लक्षण पहचानना भी आसान है। अवसाद की इस स्थिति से कोई भी प्रभावित हो सकता है। इसमें व्यक्ति का मूड थोड़ी-थोड़ी देर में बदलता रहता है, वह ज्यादा उदास रहने लगता है और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। प्रभावित व्यक्ति यादा खाना खाने लगता है और उसका वजन भी बढ़ने लगता है। दिन में थका-थका सा महसूस होना और यादा सोना भी इसके लक्षणों में शामिल है।

यह सभी लक्षण हर साल एक विशेष मौसम में दिखाई पड़ते हैं। देखने में आया है कि सैड के लक्षण सितंबर या अक्टूबर अथवा अप्रैल और मई के बीच यादतः प्रभावित करते हैं।

रोशनी में छुपा उपचार

चिकित्सक सैड के उपचार के लिए अधिकांशतः लाइट थेरेपी का उपयोग करते हैं, जो दो तरह से काम में लाई जाती है। पहली-ब्राइट लाइट थेरेपी, जिसमें रोगी को एक विशेष तरह के 'लाइट बॉक्स' के सामने आधे घंटे या इससे यादा के लिए बैठाया जाता है। और दूसरी, हल्की लाइट थेरेपी,



जो सुबह होने से पहले की रोशनी जैसी होती है और धीरे-धीरे बढ़ते हुए रोगी को सुबह का अहसास कराती है। इसके अलावा अवसादरोधी दवाएं और काउंसलिंग भी रास्ते हैं, जो रोग से उबरने में आपकी मदद कर सकते हैं। सैड से रोगमुक्त होने के पश्चात भी नियमित व्यायाम, दिनभर में ज्यादा से ज्यादा सक्रियता (खासकर सुबह के समय) की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी जाती है।

ज्यादा ठंडा दिल के लिए नहीं कूल

अगर आपको भी रोजाना ठंडी-ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक गटकने की आदत है, तो आपके लिए वॉनिंग है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि रोज एक कैन यानी 350 मिलीलीटर सॉफ्ट ड्रिंक पीने वालों में हार्ट अटैक का खतरा 20 परसेंट तक बढ़ जाता है। ये ड्रिक्स ज्यादा लेने से डायबीटीज और मोटापा बढ़ने की भी आशंका रहती है। हालांकि हफ्ते में दो सॉफ्ट ड्रिंक पीने वालों के दिल को खतरे के लक्षण नहीं दिखे हैं। वैज्ञानिकों ने 40 हजार पुरुषों पर सर्वे के बाद यह नतीजा निकाला। रोजाना सॉफ्ट ड्रिक्स या दूसरी मीठी कोल्ड ड्रिक्स लेने वालों के शरीर में खतरनाक फैट और प्रोटीन काफी बढ़ जाते हैं और अच्छे कॉलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है। यह दिल के लिए अच्छा नहीं होता। अहम बात यह है कि एक्सरसाइज जैसे फैक्टर्स से भी इसमें फर्क नहीं पड़ता। स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों के लीडर डॉ. फ्रैंक हू कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिक्स के बजाय पानी, चाय और कॉफी लेना बेहतर होता है।

वजन बढ़ती है सॉफ्ट ड्रिक्स

भारत में एक्सपर्ट डॉक्टर इस स्टडी से पूरी तरह सहमत नहीं हैं लेकिन ज्यादा कोल्ड ड्रिंक से सेहत को खतरे की बात मानते हैं। ड्रिक्स लेने का मतलब है ज्यादा कैलोरी लेना, जिससे मोटापा बढ़ सकता है जो तमाम बीमारियों की जड़ होता है। 50 मिलीलीटर मीठी सॉफ्ट ड्रिक्स से 50 एक्सट्रा कैलोरी शरीर में पहुंचती है। रोजाना 300 एमएल ड्रिंक का मतलब 150 कैलोरी ज्यादा। इससे एक

साल में 8-9 किलो वजन बढ़ सकता है।

फ्रिज में रखें ये आहार

यह बहुत जरूरी है कि सोते समय ऐसा पौष्टिक आहार ग्रहण करें जिससे हमारा पेट भरा रहे। रात में खाना खाने के बावजूद भी अगर भूख लग जाती है तो घर की फ्रिज बहुत काम आती है। क्योंकि उसमें ऐसा जरूर कुछ न कुछ होता ही है जिससे हम अपनी भूख शांत कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि फ्रिज में ऐसी कौन सी जरूरी चीजे रखें जो रात-बिरात हमारे खाने के काम आए।

फल- सेब, पीपिता, स्ट्रॉबेरी और अंगूर जैसे फल पौष्टिक तो होते ही हैं साथ ही इनको कई दिनों तक फ्रिज में भी स्टोर कर के रखा जा सकता है। इन फलों को खाने से शरीर में वसा भी कम होती है। जब भी आप जल्दी में हो या फिर थके हुए हों तो भी आप इनका सेवन कर सकते हैं।

सब्जियां- कुछ सब्जियां जैसे कि टमाटर या फिर गाजर खाने से पेट भी भरा रहता है और स्वाद में भी यह बहुत टेस्टी होते हैं। टमाटर खाने से शरीर का फैट बर्न होता है और गाजर में विटामिन ए होता है जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो इसलिए यह दोनों सब जगहों तो आपकी फ्रिज में होनी ही चाहिए।

दूध- वसा रहित दूध रात में आपकी भूख से जा रही जान को बचा सकता है। यह सेहत के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। किसी भी समय दूध को फल के साथ खाने से सेहत बनती है। दूध



में कैल्शियम पाया जाता है और वसा रहित दूध से फैट नहीं होता।

दही- यह सेहत से भरपूर दही आप या तो ऐसे ही खा सकते हैं या फिर सलाद में डाल कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप कॉलेज या ऑफिस के लिए लेट हों तब दही में नमक या चीनी मिला कर खाने से पेट भर जाता है और पेट भी सही रहता है।

नींबू- हर फ्रिज में नींबू होना बहुत जरूरी है। इसको खाने में स्वाद तो बढ़ता ही है साथ में फैट भी बर्न करता है। सलाद बना कर नींबू की कुछ बूंद डालने से स्वाद आता है और नींबू का शरबत पीने से पेट भर जाता है।

फ्रूट से फ्रेशनेस रहे कायम

त्वचा की सही तरीके से देखभाल के लिए समय की दरकार होती है, पर टाइम शेड्यूल के चलते वैसा केयर संभव नहीं हो पाता है। लेकिन सौंदर्य विशेषज्ञ मोनिका झावेरी बता रही हैं कुछ फ्रूट मॉस्क के बारे में, जिनकी मदद से आप कम समय में भी खिला चेहरा पा सकते हैं। आइए जानते हैं उन्हें..

एप्पल मास्क

सामान्य त्वचा के लिए एप्पल मॉस्क मुफीद रहता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सेब के टुकड़ों को फूड प्रोसेसर में डालें और उनके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। अब इसमें शहद मिलाएं और इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दें। अब इस मिश्रण को चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। चेहरे पर लगाने के बाद इसे 30 मिनट के लिए वैसा ही छोड़ दें और फिर धो दें। सेब में



विटामिन ए, बी और सी की बढ़िया माला होती है, लिहाजा यह एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट भी है।

ऑरेंज मास्क

मुंहासे एक सामान्य समस्या है और कुछ लोगों को

यह अक्सर परेशान करती है। खासतौर से किशोरवय के लोग इससे ज्यादा जूझते रहते हैं। मुंहासों से भरी त्वचा के लिए ऑरेंज मॉस्क बढ़िया काम करता है। इसे बनाने के लिए संतरे में एक टी-स्पून पुदीना और नींबू का रस मिलाएं और फिर इसे चेहरे पर लगाएं। इसे चेहरे पर लगाने के बाद 30 मिनट के लिए छोड़ दें और चेहरा धो लें।

जैसा कि हम जानते हैं, संतरे में विटामिन सी भरपूर होता है, इसलिए यह एंटी-ऑक्सीडेंट और जिंक का बेहतरीन स्रोत है। यह न केवल मुंहासे से बचाव करता है, बल्कि त्वचा की भीतरी सफाई कर मृत त्वचा को निकालने में भी मदद करता है। चेहरे से काले धब्बों को भी यह हटाता है। वैसे इन समस्याओं से निजात पाने के लिए संतरे के जैसे और दूसरे खट्टे फल का भी उपयोग किया जा सकता है।

स्ट्रॉबेरी मॉस्क

इस मॉस्क का उपयोग कमजोर त्वचा को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले, फके हुए स्ट्रॉबेरी का आधा कप जूस लें और इसमें एक चौथाई कप कॉर्न स्टार्च मिलाएं। लीजिए, हो गया तैयार। अब इसे चेहरे पर 30 मिनट तक लगाकर रखें, फिर इसे ठंडे पानी से धो दें। आप अपनी कमजोर त्वचा में कसावट व ताजगी पाएंगे। देखने वालों को इसमें चमक दिखाई पड़ेगी।

मोटापा बनता गर्भधारण में रुकावट

मोटापा महिलाओं को मां बनने के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर रहा है। पहले तो मोटी महिला गर्भ धारण बहुत ही मुश्किल से कर पाती है और यदि गर्भ टहर भी जाए तो उसे कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। इस लिए ध्यान रखें कि गर्भधारण करने के पहले चर्बी न बढ़ाएं। मोटापा गर्भवती महिला की जान भी ले सकता है। मोटापा पेट में पल रहे बच्चे को भी हानि पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में पेट में पल रहा बच्चा भी काफी मोटा हो जाता है। महिलाओं का मोटापा उनको बांझपन की ओर ले जा रहा है। कई शोषों से पता चला है कि मोटापा गर्भधारण करने में बहुत बड़ी अड़चन है। जो महिला मोटापे के बाद गर्भधारण कर के बच्चे को जन्म देती है उसका बच्चा भी 4 चार की उम्र तक आते आते मोटा हो जाता है। जो कि ठीक नहीं है। इस कारण आज की महिला अपने मोटापे को बढ़ने नहीं देती जयरात पड़ने पर वह सर्जरी भी करवाती है। सर्जरी के बाद उनको गर्भधारण करने के लिए कम से कम दो साल का इंतजार करना पड़ता है।



मुलहठी के मीठे उपयोग

छोटे बच्चों और बच्चों के लिए आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली वनौषधियों में एक है- मुलहठी, इसे जेटीमध, मधुक, मधुयस्ति भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लिंकोरिस कहते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों की एक दवा मुलहठी है। यह स्वाद में मधुर, शीतल, पचने में भारी, स्निग्ध और शरीर को बल देने वाली होती है। इन गुणों के कारण यह बढ़े हुए तीनों दोषों को शांत करती है।

'खॉसी-जुकाम से बढ़े हुए कफ को कम करने के लिए मुलहठी का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। बढ़े हुए कफ से गला, नाक, छाती में जलन हो जाने जैसी अनुभूति होती है, तब मुलहठी को शहद में मिलाकर चाटने से बहुत फायदा होता है।

'बड़ों के लिए मुलहठी के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिशुओं के लिए मुलहठी के जड़ को पत्थर पर पानी के साथ 6-7 बार घिसकर शहद या दूध में मिलाकर दिया जा सकता है। यह स्वाद में मधुर होती है अतः सभी बच्चे बिना झिझक के इसे चाट लेते हैं।

आमाशय की बढ़ी हुई अम्लता एवं अम्लपित्त जैसी व्याधियों में मुलहठी काफी उपयुक्त सिद्ध होती है। आमाशय के अंदर हुए ब्रण (अलसर) को मिटाने के लिए एवं पित्तवृद्धि को शांत करने के लिए मुलहठी का उपयोग होता है। मुलहठी को मिलाकर पकाए गए घी का प्रयोग करने से अलसर मिटता है।

'यह हल्की रेचक होती है। अतः पाचन के विकारों में इस के चूर्ण को इस्तेमाल किया जाता है। विशेषतः छोटे बच्चों को जब कब्ज होती है, तब हल्के रेच के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। छोटे शिशु कई बार शाम को रोते हैं। पेट में गैस के कारण उन्हें शाम के चक् पेट में दर्द होता है। उस समय मुलहठी को पत्थर पर घिसकर पानी या दूध के साथ पिलाने से पेट दर्द शांत हो जाता है।

